वर्ष 12 • अंक 249 • 12 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

शुक्रवार 6 दिसंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

चाय निर्यात बाजार के रूप में उभर रहा ईरान

विमल कुमार राय पृष्ठ 12

उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण रद्द करने के पक्ष में नहीं

डॉलर रु. 71.30 ▼ 20 पैसे | यूरो रु. 79.10 ▼ 10 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 38028 ▼ 156 रुपये | सेंसेक्स 40779.60 ▼ 70.70 | निफ्टी 12018.40 ▼ 24.80 | निफ्टी फ्यूचर्स 12047.70 ▲ 29.30 | ब्रेंट क्रूड 63.30 डॉलर ▲ 0.40 डॉलर

एक नज़र

15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट

15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक एन के सिंह की अगुआई वाले आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशों से अवगत करा दिया है। आयोग का गठन 27 नवंबर, 2017 को किया था और उसे अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक की पांच साल की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें देनी थी। 27 नवंबर, 2019 की गजट अधिसूचना के मुताबिक आयोग को वित्त वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट 30 नवंबर, 2019 तक सौंपनी थी। उसे अप्रैल 2021 से मार्च 2026 की अवधि की अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर, 2020 तक देनी है। पृष्ठ 4

हैरानी पैदा करती है मोदी की चुप्पीः चिदंबरम

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आर्थिक नरमी पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए गुरुवार को कहा कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी हैरान करने वाली है। जेल में 106 दिन रहने के बाद जमानत पर बाहर आए कांग्रेस नेता चिदंबरम ने कहा कि मोदी की चुप्पी के चलते उनके मंत्री झांसा दे रहे हैं और शेखी बघारने में लगे हैं। सरकार मान रही है कि अर्थव्यवस्था में जो समस्याएं हैं, वे चक्रीय परिस्थितियों की वजह से हैं। सरकार इस मोर्चे पर गलत साबित होगी क्योंकि वह अर्थव्यवस्था के मामले में अंधेरे में है उसे कोई जानकारी नहीं है।

एचडीएफसी एएमसी के शेयर 4 फीसदी लुढ़के

प्रवर्तक स्टैंडर्ड लाइफ द्वारा 3.1 फीसदी शेयरों की बिक्री के बाद एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के शेयरों में गुरुवार को 4 फीसदी से अधिक की गिरावट आई। यह बिक्री ऑफर फॉर सेल के जरिये की गई। न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के नियमों का पालन करने के लिए यह बिक्री की गई। कुल 65.8 लाख शेयर बिक्री के लिए रखे गए थे और 79.2 लाख शेयरों के लिए आवेदन मिले। अधिकांश बोलियां संस्थागत निवेशकों की तरफ से आई जबकि खुदरा निवेशकों के लिए रखे गए शेयरों को कम आवेदन मिले। शेयर बिक्री के लिए आधार मूल्य 3,170 रुपये रखा गया था।

एचडीएफसी बैंक की सेवा में रुकावट की जांच

निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं में इस सप्ताह लगातार दो दिन आई गड़बड़ी की रिजर्व बैंक जांच कर रहा है। इसके लिए एक टीम गठित की गई है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एमके जैन ने गुरुवार को कहा कि उनकी टीम इसके कारणों की पहचान करेगी और यह पता लगाएगी कि एचडीएफसी बैंक को क्या निर्देश दिया जा सकता है। तकनीकी खामियों के कारण बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग में सोमवार और मंगलवार को दिक्कत आई थी।

प्याज की कीमतों पर अमित शाह ने की बैठक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्याज की आसमान छूती कीमतों के बारे में चर्चा करने के लिए गुरुवार को केंद्रीय मंत्रियों तथा शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस बैठक में रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिया। बैठक में मंत्रिमंडलीय सचिव राजीव गौबा और प्रधानमंत्री के सलाहकार पीके सिन्हा भी उपस्थित थे।

महंगाई से थमे आरबीआई के कदम

रीपो दर को 5.15 फीसदी पर रखा बरकरार आम बजट का है आरबीआई को इंतजार

चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर अनुमान को 6.1 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया

अनूप रॉय
मुंबई, 5 दिसंबर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बाजार को चकित करते हुए आज दरों में कटौती पर 'अस्थायी विराम' लगा दिया। आरबीआई अब दरों पर किसी तरह का निर्णय करने से पहले फरवरी में पेश होने वाले आम बजट में सरकार के उपायों तथा मुद्रास्फीति को लेकर ज्यादा स्पष्ट तस्वीर का इंतजार करेगा।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने एकमत से रीपो दर को 5.15 फीसदी पर बरकरार रखने का निर्णय किया। हालांकि आरबीआई ने विकास दर और मुद्रास्फीति के अनुमानों में बदलाव किया है।

केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर अनुमान को 6.1 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। इसी तरह दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति के 3.5-3.7 फीसदी से बढ़कर 4.7-5.1 फीसदी के दायरे में रहने का अनुमान लगाया है। विनिर्माण गतिविधियों में नरमी की वजह से क्षमता उपयोग में भी गिरावट आई है और यह पहली तिमाही के 73.6 फीसदी से घटकर दूसरी तिमाही में 68.9 फीसदी रह गई।

हालांकि दास ने कहा कि आरबीआई वृद्धि दर में नरमी से ज्यादा चिंतित नहीं है। दास ने कहा, 'हम व्यापक स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आरबीआई ने भी दरों में लगातार कटौती की है तथा तरलता की स्थिति भी बेहतर बनी हुई है। दरों में कटौती का भी लाभ दिख रहा है। हमें दरों में कटौती का और लाभ देखने के लिए कुछ समय इंतजार करना होगा। इसलिए मौद्रिक नीति समिति ने फिलहाल दरों को यथावत बनाए रखने का निर्णय किया।'

(शेष पृष्ठ 3 पर)

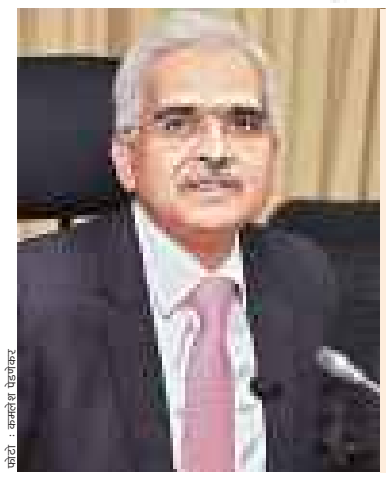

फोटो : कमलेश पेडणेकर

उद्योग का क्षमता उपयोग 2008 के बाद सबसे निचले स्तर पर

क्षमता उपयोग (%)

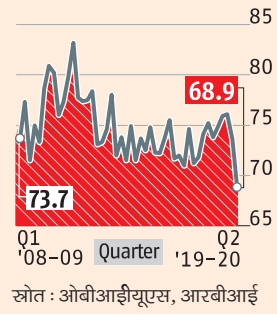

स्रोत : ओबीआईयूएस, आरबीआई

- आरबीआई ने रीपो दर में कटौती पर लगाया अस्थायी विराम
- महंगाई दर बढ़ने की आशंका में आरबीआई ने रीपो दर में नहीं की कटौती
- फरवरी से अब तक आरबीआई ने की है रीपो दर में 135 आधार अंक की कटौती
- वित्तीय और मौद्रिक नीतियों के बीच है बेहतर समन्वय
- आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक उदार रुख बनाए रखेगा

उद्योग में क्षमता उपयोग निचले स्तर पर

भारत के विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता इस्तेमाल साल 2008 के बाद के निचले स्तर पर पहुंच गया है। सितंबर तिमाही में यह 68.9 फीसदी रह गया। मौद्रिक नीति समिति के बयान में कहा गया है, विनिर्माण गतिविधियों में नरमी 2019-20 की दूसरी तिमाही में क्षमता इस्तेमाल घटकर 68.9 फीसदी पर आ गई जो पहली तिमाही में 73.6 फीसदी रही थी। ये चीजें भारतीय रिजर्व बैंक के ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री और क्षमता इस्तेमाल के सर्वेक्षण में सामने आई। दो तिमाही पहले (मार्च 2019) यह 6 साल के उच्चस्तर 76 फीसदी पर था। ये आंकड़े उद्योग की मौजूदा मंदी की गंभीरता बताते हैं। 73.6 फीसदी से घटकर 68.9 फीसदी पर आना, यानी इसमें 4.7 फीसदी की तीव्र गिरावट भी अप्रत्याशित है। पृष्ठ 3

टाटा ट्रस्ट्स मामले में अधिकारियों से जवाब तलब

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 5 दिसंबर

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने टाटा ट्रस्ट्स का पंजीकरण रद्द करने के मामले से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया है। कर विभाग पंजीकरण रद्द करने की तिथि के बारे में इन अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई थी।

टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस में टाटा ट्रस्ट्स कर 66 फीसदी हिस्सेदारी है। कर विभाग ने टाटा ट्रस्ट्स के तहत काम करने वाले छह ट्रस्टों का पंजीकरण 31 अक्टूबर को रद्द कर दिया गया था। इन ट्रस्टों ने इस फैसले को पिछले महीने आय कर अपील पंचाट में चुनौती दी थी। पंजीकरण रद्द होने के कारण टाटा ट्रस्ट्स को नए कर प्रावधान के तहत अच्छा खासा कर देना होगा। परोपकारी संस्थाओं से जुड़ा यह प्रावधान जून 2016 में लाया गया था।

अलबत्ता टाटा ट्रस्ट्स का मानना है कि उनका पंजीकरण पिछली तारीख से रद्द होना चाहिए क्योंकि उसने कानून के प्रभाव में आने से एक साल पहले ही परोपकारी संस्था के रूप में अपने पंजीकरण को छोड़ने की पेशकश की थी।

सूत्रों के मुताबिक सीबीडीटी चाहता है कि इस मामले से जुड़े अधिकारियों को यह स्पष्टीकरण देना चाहिए कि निर्धारित समयावधि के दौरान इसका निपटारा क्यों नहीं किया गया। साथ ही उनसे यह भी पूछा गया है कि टाटा ट्रस्ट्स के पंजीकरण पर 2015 में नोटिस भेजे जाने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

सीबीडीटी यह जानने में भी जुटा है कि क्या टाटा ट्रस्ट्स के मामले में कानून के विशेष प्रावधान का सहारा लिया गया। परोपकारी संस्थाओं के कराधान से जुड़े पहलुओं से निपटने के लिए एक अलग शाखा है। लेकिन यह मामला कई वर्षों से सलुझाया नहीं जा सका और इसे 2018 में ही कर विभाग की आकलन शाखा को सौंपा गया। इसके बाद ही शाखा ने कर आकलन के लिए इसे दोबारा खोला।

सूत्रों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों से जवाब मिलने के बाद आय कर विभाग अपील पंचाट में अपनी दलील रखेगा। कर विभाग अब तक यही कहता आया है कि अगर उसने किसी परोपकारी संस्था का पंजीकरण रद्द नहीं किया है और वह खुद अपना यह दर्जा छोड़ती है तो यह वैध नहीं है।

अक्टूबर के आदेश में कर विभाग ने आय कर कानून की धारा 115 (टीडी) लागू की थी जो नया और विशेष प्रावधान है। इसके तहत अगर किसी ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द होता है तो उसे पिछले छूट की आय पर कर का भुगतान करना होगा। साथ ही अगर ट्रस्ट को गैर परोपकारी ट्रस्ट में बदला जाता है या विलय किया जाता है या उसे भंग किया जाता है और वह परिसंपत्तियों/देनदारी के हस्तांतरण में नाकाम रहता है तो उसे अतिरिक्त आय कर देना होगा।

कर विभाग ने जमशेदजी टाटा ट्रस्ट, आरडी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट, टाटा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट और नवजबाई रतन टाटा ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द किया था। ये मुख्य शेयरधारक ट्रस्ट नहीं हैं लेकिन समूह की मूल कंपनी टाटा संस में उनके 39,000 शेयर हैं। टाटा ट्रस्ट्स के मुख्य घटक सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट्स और सर रतन टाटा ट्रस्ट हैं।

- छह ट्रस्टों का पंजीकरण किया गया था रद्द
- टाटा ट्रस्ट्स ने अपील पंचाट में दी है चुनौती
- जल्द शुरू होने वाली है सुनवाई

जीएसटी : 5 की जगह 6 फीसदी लगेगा कर!

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 5 दिसंबर

- 5 फीसदी के स्लैब को बढ़ाकर 6 फीसदी करने से प्रति माह 1,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व मिलेगा
- कर छूट वाली वस्तुओं को जीएसटी दायरे में लाने की संभावना तलाश रही समिति
- सिगरेट और एयरेटेड पेय पर मुआवजा उपकर बढ़ाने का विचार
- महाराष्ट्र ने सोने पर जीएसटी 3 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी करने का दिया सुझाव

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में आ रही कमी को बढ़ाने के लिए गठित राजस्व संवर्द्धन समिति जीएसटी के 5 फीसदी के स्लैब को बढ़ाकर 6 फीसदी करने सहित विभिन्न उपायों का मूल्यांकन कर रही है। इसके साथ ही सिगरेट और एरेटेड पेय पर उपकर बढ़ाने और कई चीजों को छूट वाली सूची से बाहर करने पर भी विचार किया जा रहा है।

अगर प्रतिमाह जीएसटी संग्रह को 1 लाख करोड़ रुपये मानें तो 5 फीसदी के स्लैब को बढ़ाकर 6 फीसदी करने से सरकार को हर महीने करीब 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जीएसटी के कुल संग्रह में 5 फीसदी स्लैब से करीब 5 फीसदी राजस्व मिलता है।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, '5 फीसदी के स्लैब को 6 फीसदी करने के पीछे तर्क यह भी है कि इससे राज्य और केंद्र को 3-3 फीसदी जीएसटी प्राप्त होगा। कुछ राज्यों का तर्क है कि इससे कर की दर में 20 फीसदी का इजाफा हो जाएगा। लेकिन मूल्य के लिहाज से यह ज्यादा नहीं है।' समिति अगले हफ्ते फिर बैठक करेगी। 5 फीसदी के कर दायरे में फिलहाल आवश्यक जिंस और बुनियादी कपड़े और खाद्य पदार्थ आदि आते हैं। सरकार को करीब 60 फीसदी राजस्व 18 फीसदी कर दायरे में आने वाली वस्तुओं से मिलती है। पीडब्ल्यूसी इंडिया के पार्टनर प्रतीक जैन ने कहा, 'अगगर सरकार मानती है कि दर में इजाफा करना ही एकमात्र विकल्प है तो चुनिंदा तरीके से कुछ आइटम पर जीएसटी बढ़ाने का विचार करना चाहिए और बेहतर होगा कि वह 18 फीसदी के स्लैब को बढ़ाकर 19 फीसदी कर दे।'

समिति कुछ अन्य चीजों को भी जीएसटी के दायरे में लाने की संभावना तलाश रही है। जैन ने कहा, 'कर छूट वाली चीजों पर कर लगाने से तब तक बहुत ज्यादा राजस्व प्राप्त नहीं होगा जब तक कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को कर दायरे में लाने का विचार नहीं करती है।' इसके अलावा समिति सिगरेट और एयरेटेड पेय पर भी मुआवजा उपकर दर में इजाफा करने पर विचार कर रही है। करीब 34 वस्तुएं अहितकर और लक्जरी श्रेणी में शामिल हैं जिन पर 28 फीसदी की दर से कर लगता है और साथ ही कुछ पर अतिरिक्त उपकर भी वसूला जाता है। इनमें वाहन, सिगरेट और एयरेटेड पेय शामिल हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल वाहन पर उपकर बढ़ाने की संभावना नहीं है लेकिन सिगरेट और एयरेटेड पेय पर उपकर बढ़ाया जा सकता है।

इस समय 65 मिमी की मोटाई तक की प्रति हजार सिगरेट पर 5 प्रतिशत उपकर और 2,076 रुपये कर लगते हैं। इसी तरह 75 एमएम तक मोटी प्रति हजार सिगरेट पर 5 प्रतिशत उपकर के साथ 3,668 रुपये लगते हैं। वास्तव में दूसरी तरह की सिगरेट पर 36 सिगरेट के साथ 4,170 रुपये शुल्क लगता है। दूसरी तरफ एयरेटेड पेय पर कुल 40 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जिनमें 28 प्रतिशत कर और 12 प्रतिशत अतिरिक्त उपकर होते हैं। राज्यों ने जो उपाय सुझाए हैं, उनमें महाराष्ट्र ने सोना पर जीएसटी दर 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही राज्य ने उन करदाताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देने की सलाह दी है, जिन्होंने दो लगातार महीनों से रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं।

व्यापार गोष्ठी

कॉल दरों में इजाफा कितना जरूरी?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201 या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या रीपो दर को यथावत रखने का आरबीआई का निर्णय उचित है

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या डेटा संरक्षण विधेयक से लोगों की निजता होगी सुरक्षित?	हां	68.75%
	नहीं	31.25%

चीन के कई ऐप पर संसदीय समिति की नजर

करण चौधरी और नेहा अलावधी
बेंगलूरु/नई दिल्ली, 5 दिसंबर

टिकटॉक, हेलो, बिगो लाइव सहित चीन के दूसरे अन्य सोशल मीडिया ऐप्लीकेशन (ऐप) महिलाओं के सशक्तीकरण पर गठित संसद की स्थायी समिति की रडार पर आ गए हैं। इस समिति ने ऑनलाइन माध्यमों में महिलाओं एवं किशोर के उत्पीड़न एवं छेड-छाड़ रोकने के लिए प्रयास तेज कर दिया है।

इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि समिति इन सभी मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाना चाहती है। समिति इन कंपनियों से यह जानने की कोशिश करेगी कि ऑनलाइन अपराध एवं छेड-छाड़ रोकने के लिए उन्होंने क्या उपाय किए हैं। चीन के इन ऐप्लीकेशनों पर युवाओं की सुरक्षा से जुड़े मामले कई बार सरकारी एजेंसियों के समझ उठे हैं और न्यायालय तक में इनकी गूंज सुनाई दी है। संसद की यह स्थायी समिति यह समझना और इनकी समीक्षा करना चाहती है कि इन कंपनियों ने सुरक्षा के तमाम मुद्दों पर क्या कारगर कदम उठाए हैं।

समिति ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप सहित सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों से ऐसे मामले रोकने के लिए कदम उठाने के लिए कह रही है। गुरुवार को समिति के सदस्यों ने फेसबुक के प्रतिनिधियों से पूछा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध, छेड-छाड़ और उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ आदि रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। समिति ने उन्हें ऐसी आपत्तिजनक सामग्री सक्रियता दिखाते हुए हटाने के लिए कहा है, जिनकी तरफ किसी उपयोगकर्ता (ऐप) ने ध्यान दिलाया है। सूत्रों के अनुसार समिति के सदस्यों ने इस बात का भी जिक्र किया कि आपत्तिजनक साम्रगी हटाने में सोशल मीडिया कंपनियां काफी वक्त लेती हैं, इसलिए इसमें थोड़ी सक्रियता दिखाने की जरूरत है। माना जा रहा है कि फेसबुक ने सांसदों के प्रशिक्षण और उन्हें संवेदनशील बनाने की पेशकश की है। फेसबुक में लोक नीति निदेशक अंखी दास के नेतृत्व वाली टीम ने फेसबुक द्वारा महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित होने से रोकने के उठाए गए कदमों के बारे में समिति को जानकारी दी।

दास ने कहा, 'हम यह पूरी तरह समझते हैं कि फेसबुक और हमारे ऐप के लिए यह मामला कितना महत्त्वपूर्ण है। हम अपने सभी माध्यमों को महिलाओं के लिए लिहाज से सुरक्षित और अनुकूल बनाने के प्रति पूरी तरह गंभीर हैं। ऐसे मामलों से निपटने के लिए हम लगातार कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) का सहारा ले रहे हैं।'

सोशल मीडिया क्षेत्र पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए न्यूनतम आयु 13 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष किए जाने की जरूरत है। विशेषज्ञों के अनुसार नाबालिग के खातों के लिए अभिभावक की सहमति के साथ ही उम्र की प्रामाणिकता जांचने के लिए भी सोशल मीडिया पर एक पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। लोकलसर्किल्स के संस्थापक एवं चेयरमैन सचिन तपड़िया कहते हैं, 'वास्तविक पहचान अनिवार्य बनाने और आपत्तिजनक सामग्री हटाने में तत्परता दिखाने से सोशल मीडिया पर महिलाओं एवं बच्चों के उत्पीड़न के 80 प्रतिशत तक मामले हल हो जाएंगे। यहां पर सवाल यह नहीं हे कि ये कंपनियां इन मामलों को राकने में सक्षम हैं या नहीं बल्कि चर्चा उनकी मंशा को लेकर है। मुझे उम्मीद है कि ये कंपनियां सुरक्षा एवं जवाबदेही को व्यावसायिक उद्देश्यों के मुकाबले तरजीज देंगी।'

- टिकटॉक, हैलो, बिगो लाइव पर सरकार की पैनी नजर
- महिला सशक्तीकरण पर गठित समिति इनके प्रतिनिधियों को बुलाने पर कर रही विचार
- समिति ने गुरुवार को फेसबुक के प्रतिनधियों से महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ उत्पीपड़ने रोकने के उपायों के बारे में पूछा
- आपत्तिजनक सामग्री हटाने में सोशल मीडिया कंपनियां लेती हैं अधिक समय

खबरों में रहे स्टॉक

येस बैंक

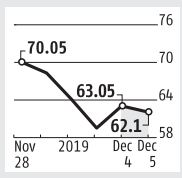

मूडीज ने बैंक की रेटिंग घटाई

₹ 63.05 पिछला बंद भाव
₹ 62.10 आज का बंद भाव
▼ 1.51 %

इंटरग्लोब एविएशन

वित्त वर्ष 2020 के लिए क्षमता वृद्धि का अनुमान घटाया

₹ 1,405.20 पिछला बंद भाव
₹ 1,320.20 आज का बंद भाव
▼ 6.05 %

जिंदल स्टील ऐंड पावर

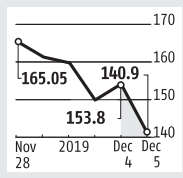

निफ्टी धातु सूचकांक में सबसे अधिक गिरने वाला शेयर

₹ 153.80 पिछला बंद भाव
₹ 140.90 आज का बंद भाव
▼ 8.39 %

व्हर्लपूल ऑफ इंडिया

बाजार पूंजीकरण के मोर्चे पर शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल

₹ 2,313.30 पिछला बंद भाव
₹ 2,406.05 आज का बंद भाव
▲ 4.01 %

भारती एयरटेल

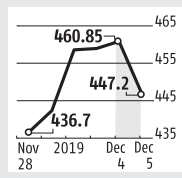

डेट एवं इक्विटी के जरिये 3 अरब डॉलर जुटाने की योजना को बोर्ड की मंजूरी

₹ 460.85 पिछला बंद भाव
₹ 447.20 आज का बंद भाव
▼ 2.96 %

संक्षेप में

मूडीज ने येस बैंक की रेटिंग घटाई

वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने गुरुवार को येस बैंक की दीर्घावधि विदेशी मुद्रा रेटिंग को 'बीए3' से घटाकर 'बी2' कर दिया है। एजेंसी ने संभावित दबावग्रसत परिसंपत्तियों एवं बफर की कम खपत के कारण वित्त पोषण एवं नकदी प्रवाह पर दबाव बढ़ने की आशंका में यह कार्रवाई की है। इससे बैंक के एकल क्रेडिट प्रोफाइल पर जोखिम बढ़ सकता है। मूडीज का मानना है कि सितंबर 2019 के अंत में येस बैंक का कॉमन इक्विटी टियर-1 (सीईटी) अनुपात 8.7 फीसदी था। यदि बैंक अगले कुछ महीनों में पूंजी नहीं जुटाएगा तो वह काफी दबाव में होगा। येस बैंक को नई इक्विटी पूंजी के जरिये 2 अरब डॉलर तक निवेश करने के लिए कई वित्तीय निवेशकों से पेशकश मिली है। पूंजी निवेश कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए बैंक के निदेशक मंडल की बैठक 10 दिसंबर को होगी। *बीएस*

सरकार ने एनसीएलटी के आदेश को चुनौती दी

सरकार ने राष्ट्रीय एनसीएलटी के आईबीसी और कंपनी कानून के तहत दायर किए जाने वाले सभी मामलों में कंपनी कार्य मंत्रालय को एक पक्ष बनाने के आदेश को एनसीएलएटी में चुनौती दी है। याचिका में सरकार ने कहा है कि एनसीएलटी के दिल्ली के प्रधान पीठ का यह आदेश उसके अधिकार और न्याय क्षेत्र से बाहर है। *भाषा*

मैनकाइंड की नजर अधिग्रहण पर

जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किसी कंपनी के अधिग्रहण की संभावनाएं तलाश रही कंपनी

सोहिनी दास
मुंबई, 5 दिसंबर

भारत सेरम्स ऐंड वैक्सिन के साथ बातचीत विफल रहने के बाद मैनकाइंड फार्मा जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में खरीदारी के लिए गंभीरतापूर्वक संभावनाएं तलाश रही है। कंपनी का मानना है कि उसके जैव प्रौद्योगिकी कारोबार के लिए एक विनिर्माण केंद्र काफी महत्त्वपूर्ण होगा और वह इस क्षेत्र में विलय-अधिग्रहण की योजना बना रही है। इस बीच, मैनकाइंड एक सिंथेटिक महिला हार्मोन उत्पाद को बाजार में उतारने के लिए तैयार है। इसके साथ ही मैनकाइंड सिंथेटिक महिला हार्मोन उत्पाद बनाने वाली भारत की पहली और ऐबट के बाद विश्व की दूसरी कंपनी बन जाएगी।

गंभीर चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित करने वाली इस कंपनी ने हाल में मधुमेह और हृदयरोग जैसे गंभीर उपचार क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही कंपनी अनुसंधान एवं विकास (आरऐंडडी) पर अपने कुल कारोबार का 5 फीसदी खर्च कर रही है। अधिकांश आरऐंडडी खर्च बायोसिमिलर पर किया जाता है। हालांकि 5,600 करोड़ रुपये के कारोबार वाली मैनकाइंड जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनी दवाएं भी उतारना चाहती है और इसलिए वह विलय एवं अधिग्रहण की संभावनाएं तलाश रही है।

मैनकाइंड फार्मा के संस्थापक एवं चेयरमैन आरसी जुनेजा ने कहा, 'जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए हम विलय-अधिग्रहण के जरिये वृद्धि हासिल करना चाहते हैं। हमारी नजर किसी उपयुक्त कंपनी के अधिग्रहण पर है जिससे हमें ब्रांड के साथ-साथ विनिर्माण संयंत्र भी हासिल हो सके। हम नपुंसकता श्रेणी में अपनी जैव प्रौद्योगिकी दवा उतारने की योजना बना रहे है। हम भारत सेरम्स के साथ बातचीत कर रहे थे लेकिन बातचीत सफल नहीं रही।'

मैनकाइंड फार्मा का मानना है कि अजैव प्रौद्योगिकी विनिर्माण संयंत्र उसके जैव प्रौद्योगिकी कारोबार के लिए काफी महत्त्वपूर्ण है और इसलिए वह अधिग्रहण के जरिये उसे हासिल करना चाहती है। जुनेजा ने कहा कि यदि उन्हें कोई उपयुक्त सौदा नहीं मिला तो वे आंतरिक आरऐंडडी पर ध्यान केंद्रित करेंगे और खुद अपना संयंत्र स्थापित करेंगे। फिलहाल कंपनी के पास 21 विनिर्माण संयंत्र मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश में उसके पाउंटा साहिब संयंत्र को फरवरी में अमेरिकी औषधि नियामक यूएसएफडीए से मंजूरी मिली थी और अब वहां अमेरिकी बाजार के लिए परीक्षण बैच की तैयारी हो रही है।

बायोसिमिलर क्षेत्र में भी कंपनी रुमैटोलॉजी श्रेणी में दवा विकसित कर रही है। उसके पास 400 वैज्ञानिकों के साथ दमदार आरऐंडडी टीम है और वह मधुमेह उपचार श्रेणी में भी नई दवाओं पर काम कर रही है।

इस बीच, मैनकाइंड फार्मा गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं के उपचार के लिए ड्रायडोजेस्टेरोन युक्त दवा विकसित करने वाली भारत की पहली और विश्व की दूसरी कंपनी बन गई है। जुनेजा ने दावा किया कि भारत में इस दवा का बाजार करीब 400 करोड़ रुपये का है जहां केवल ऐबट का एकाधिकार है।

जैव प्रौद्योगिकी पर जोर

- जैव प्रौद्योगिकी एवं बायोसिमिलर दवाओं के लिए आरऐंडडी पर कंपनी का जोर
- कंपनी अपने जैव प्रौद्योगिकी कारोबार के लिए विनिर्माण संयंत्र को अहम मानती है
- नपुंसकता के उपचार की जैव प्रौद्योगिकी दवा तैयार करने की योजना
- सिंथेटिक महिला हार्मोन बनाने वाली देश की पहली और विश्व की दूसरी कंपनी बनी मैनकाइंड

कार्वी मामले से ब्रोकिंग उद्योग में भरोसे का संकट

समी मोडक और सचिन मामबटा
मुंबई, 5 दिसंबर

कार्वी के घोटाले ने 15,000 करोड़ रुपये वाले देसी ब्रोकिंग उद्योग में भरोसे का संकट खड़ा कर दिया है और कई निवेशक अपने डीमैट खाते में प्रतिभूतियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। चिंता दूर करने के लिए ज्यादातर ब्रोकरेज अपने-अपने क्लाइंटों से संपर्क कर रहे हैं और क्लाइंटों के फंड के इस्तेमाल और प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के मामले में अपना पक्ष सामने रख रहे हैं। इस बीच, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों को शेयरों के पे-इन, पे-आउट को लेकर चौकस रहने को कहा है और पावर ऑफ अटॉर्नी के इस्तेमाल को लेकर सतर्क किया है।

हैदराबाद की कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के घटनाक्रम से यह चिंता बढ़ी है, जिसका ब्रोकिंग लाइसेंस क्लाइंटों की 2,300 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों के दुरुपयोग के कारण निलंबित कर दिया गया है। कम मशहूर अन्य ब्रोकरों ने भी ऐसी ही गड़बड़ी के कारण नियामक के कोप का सामना किया है और और ब्रोकर की अभी सेबी जांच कर रहा है। केआर चोकसी के प्रबंध निदेशक देवेन चोकसी ने कहा, इस तरह की घटना से निवेशक हिल गए हैं। आज कार्वी का मामला है, कल किसी और के यहां हो सकता है। काम के मौजूदा प्रवाह में ब्रोकर क्लियरिंग व कस्टोडियन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वहां गड़बड़ी की गुंजाइश है। इन प्रक्रियाओं पर दोबारा नजर डालने की दरकार है ताकि भविष्य में ऐसे घोटाले को टाला जा सके। हाल तक ब्रोकिंग समुदाय की तरफ से प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग या अन्य सक्रिय क्लाइंटों के लिए जमानत के तौर पर क्लाइंटों की प्रतिभूतियों को गिरवी रखना आम था। कथित तौर पर कार्वी अपने क्लाइंटों की प्रतिभूतियों के इस्तेमाल के जरिए अन्य कारोबारी जरूरतों के लिए रकम जुटाने के लिए काफी आगे बढ़ गई।

बिजनेस स्टैंडर्ड ने जीरोधा, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, शेयरखान, एडलवाइस ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल और अपस्टॉक्स से बात की। ज्यादातर ब्रोकिंग फर्मों का कहना है कि वे या तो पूरी तरह से मार्जिन फंडिंग में नहीं हैं या क्लाइंट के खातों को अलग करना सुनिश्चित करते हैं।

हुंडई भारतीय बाजार में उतारेगी फ्यूल सेल कार

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 5 दिसंबर

कार बनाने वाली कोरिया की प्रमुख कंपनी हुंडई भारतीय बाजार में फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारने की योजना बना रही है। कंपनी अपनी इस योजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पहले ही शुरू कर चुकी है।

हुंडई नेक्सो भारतीय बाजार में आने वाली संभवत: पहला फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन होगा। कंपनी दावा करती है कि नेक्सो हाइड्रोजन से चलने वाला विश्व का पहला एसयूवी है और उसका रेंज करीब 380 मील है जो अन्य फ्यूल सेल अथवा इलेक्ट्रिक वाहन के लिए सर्वाधिक है।

हुंडई मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी एसएस किम ने कहा, 'मानवता की प्रगति के लिए शून्य उत्सर्जन के साथ मोबिलिटी हमारी जिम्मेदारी है और यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए दीर्घावधि सकारात्मक बदलाव लाने के दृष्टिकोण का हिस्सा है। हमने फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक कार को भारतीय बाजार में उतारने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया है। हम शून्य उत्सर्जन मोबिलिटी के साथ बेहतरीन समाधान लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

हुंडई ने मंगलवार को वर्ष 2025 के लिए अपनी रणनीति 'स्ट्रैटेजी 2025' की घोषणा की थी। इसके तहत कंपनी ने सालाना 6,70,000 इलेक्ट्रिक वाहन बेचने का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने कहा है, 'हमारा लक्ष्य कोरिया, अमेरिका, चीन एवं यूरोप में 2030 तक और 2035 तक भारत एवं ब्राजील जैसे उभरते बाजारों को इलेक्ट्रिक करने का है।'

गति में ऑलकार्गो की हिस्सेदारी

अवश्य ग्रुप का हिस्सा ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने गति लिमिटेड में 44.64 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करते हुए एक्सप्रेस लॉजिस्टिक खंड में कदम रखा है। ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स के संस्थापक और चेयरमैन शशि किरण शेट्टी ने बताया कि यह हिस्सेदारी खरीद 10 प्रतिशत प्रवर्तक शेयरधारिता का संयोजन है। इससे 26 प्रतिशत की खुली पेशकश होगी और शेष तरजीही शेयरों के जरिये की जाएगी। इससे कुल सौदे का आकार 416 करोड़ रुपये हो जाएगा। वर्ष 1989 में महेंद्र अग्रवाल द्वारा स्थापित गति भारत में तीव्र वितरण की अगुआ रही है। वर्तमान में गति विभिन्न प्रकार की पेशकश करती है जिसमें तीव्र वितरण से लेकर तीसरे पक्ष के संचालन तक की सुविधा शामिल है। सितंबर 2019 तक कंपनी में गति के प्रवर्तक और समूह प्रवर्तक की हिस्सेदारी 17.8 प्रतिशत बैठती है। *बीएस*

मुनाफे के मोर्चे पर पेप्सिको से आगे कोका कोला

अर्णव दत्ता
नई दिल्ली, 5 दिसंबर

दो प्रमुख कोला कंपनियों- कोका कोला और पेप्सिको- ने वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व वृद्धि दर्ज की लेकिन लाभप्रदता के मोर्चे पर उनकी राह अलग दिख रही है। साल के दौरान कोका कोला इंडिया के मुनाफा मार्जिन में सुधार हुआ जबकि उसकी प्रमुख प्रतिस्पर्धी पेप्सिको का मुनाफा मार्जिन काफी कम है।

कंपनी रजिस्ट्रार के आंकड़ों से पता चलता है कि कोका कोला इंडिया का शुद्ध मुनाफा मार्जिन बढ़कर 27.4 फीसदी हो गया जो 2017-18 में 26.3 फीसदी था। कंपनी ने समेकित स्तर पर 2,311 करोड़ रुपये के परिचालन मुनाफे के साथ 632 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। कोका कोला इंडिया के प्रमुख ब्रांडों में थम्सअप, स्प्राइट और कोक शामिल हैं।

पेप्सिको चार वर्षों तक घाटे में रहने के बाद 2017-18 में मुनाफा दर्ज किया था। वर्ष 2018-19 में भी उसने मुनाफा दर्ज किया लेकिन उसका शुद्ध मुनाफा मार्जिन महज 0.2 फीसदी रहा। कंपनी ने 6,253 करोड़ रुपये के परिचालन राजस्व पर 12.64 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान दर्ज किया। शुद्ध मुनाफा मार्जिन कंपनी के शुद्ध मुनाफा और राजस्व का अनुपात होता है। माउंटेन ड्यू, मिरिंडा और ट्रॉपिकाना स्लाइस जैसे शीतल पेय बनाने वाली कंपनी पेप्सिको के मार्जिन में 2017-18 में तेजी दर्ज की गई थी जबकि उससे पहले 2011-12 से ही वह घाटा दर्ज कर रही थी। कंपनी का शुद्ध लाभ बढ़कर 203 करोड़ रुपये हो गया जो वर्ष 2016-17 में 148 करोड़ रुपये था।

कंपनी के अनुसार, वर्ष 2017-18 में पेप्सिको के मुनाफे में तेजी की मुख्य वजह ड्यूक ब्रांड के बेवरिजेस बनाने वाले एक पुराने संयंत्र की भूमि की बिक्री रही। पेप्सिको इंडिया के प्रवक्ता ने कंपनी के एकल वित्तीय प्रदर्शन के बारे में कहा कि वास्तव में 2018-19 में उसका कर बाद मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 67 फीसदी बढ़ा। उन्होंने कहा कि एकल आधार पर पेप्सिको ने 2018-19 में 36 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान पेप्सिको के परिचालन राजस्व में उल्लेखनीय गिरावट आई क्योंकि वह अपने फ्रैंचाइजी साझेदारों को बॉटलिंग संयंत्र बेच रही थी। हालांकि सालाना आधार पर कंपनी के परिचालन राजस्व में 2.4 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई लेकिन वह पांच पहले के 8,130 करोड़ रुपये के मुकाबले काफी कम है। उसके राजस्व आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकांश बिक्री स्नैकिंग एवं पोषण कारोबार से हुई जहां लेज, डोरिटोज और क्वेकर जैसे ब्रांड शामिल हैं।

पेप्सिको के प्रवक्ता के अनुसार, प्रमुख उत्पादों के दमदार प्रदर्शन के कारण पिछले साल राजस्व वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने कहा, 'मुख्य तौर पर फूड कारोबार में ई-कॉमर्स और क्षमता की अधिक उपयोगिता के जरिये वितरण, विस्तार एवं लाभ पर ध्यान केंद्रित किए जाने से लागत बचाने में मदद मिली। दमदार उत्पादकता डिलीवरी से महंगाई जैसी चुनौतियों से निपटने में मदद मिली।' कोका कोला इंडिया किसी भी उत्पाद का उत्पादन अथवा विपणन नहीं करती है और उसे प्रमुख उत्पादों के फॉर्मूलेशन स्वामित्व के लिए प्राप्त रॉयल्टी से प्रमुख आमदनी होती है। वर्ष 2017-18 में गिरावट के कार कंपनी के परिचाल राजस्व में 9.7 फीसदी की वृद्धि हुई है।

दिग्गज कोला कंपनियों की जंग

■कोका कोला इंडिया* ■पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स #

दोनों कंपनियों ने राजस्व में वृद्धि दर्ज की
परिचालन राजस्व, करोड़ रुपये में

2014-15	1,755	8,130
2015-16	1,757	7,217
2016-17	2,135	6,626
2017-18	2,107	6,106
2018-19	2,311	6,253

मुनाफे के मोर्चे पर पेप्सिको की चुनौतियां बरकरार
शुद्ध लाभ, करोड़ रुपये में

2014-15	504	-177
2015-16	474	-538
2016-17	485	-148
2017-18	554	203**
2018-19	632	12.6

पेप्सिको के लिए लाभप्रदता लगातार चिंताजनक
शुद्ध लाभ मार्जिन, फीसदी में

2014-15	28.7	-2.2
2015-16	27.0	-7.5
2016-17	22.7	-2.2
2017-18	26.3	***
2018-19	27.4	0.002

*मुख्य रूप से फॉर्मूलेशन पर रॉयल्टी से प्राप्त आय #उत्पादों का विनिर्माण एवं विपणन भी शामिल
एकमुश्त लाभ सहित * तुलना नहीं की जा सकती

स्रोत: कंपनी रजिस्ट्रार

बीएस बातचीत

मंदी भी हो सकती है वरदान

अशोक लीलैंड में करीब 14 वर्षों तक और बी2बी श्रेणी में दो दशक से अधिक समय तक काम करने के बाद **विनोद दासारी** ने रॉयल एनफील्ड के सीईओ के तौर पर बी2सी श्रेणी में कदम रखा है। दासारी ने **टीई नरसिम्हन** से बातचीत में रॉयल एनफील्ड के संचालन और भारत से एक वैश्विक उपभोक्ता ब्रांड बनाने की योजना के बारे में चर्चा की। मुख्य अंश:

आप वाणिज्यिक वाहन से मोटरसाइकल की ओर कैसे आ गए?
यह काफी रोमांचक है। यह केवल उत्पाद का सवाल नहीं है बल्कि यह एक ब्रांड और उत्पाद की कहानी है। मेरे लिए सीखने का यह एक जबरदस्त अनुभव है। मैं इसका पूरा मजा ले रहा हूं। भारत से एक वैश्विक उपभोक्ता ब्रांड तैयार करने की चुनौती मुझे सबसे अधिक रोमांचित करती है।

आपने यह जिम्मेदारी ऐसे समय में ली है जब दोपहिया वाहन उद्योग चुनौतियों से जूझ रहा है। उससे आप कैसे निपटेंगे?
रॉयल एनफील्ड में हम दीर्घावधि रणनीति तैयार करेंगे। हमारी नजर एक वैश्विक उपभोक्ता ब्रांड बनने पर है। इसलिए लघु अवधि को लेकर हम अधिक चिंतित नहीं है। कभी-कभी मंदी भी हमारे लिए वरदान हो सकती है। यदि आप कुछ चीजों को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए यह सही समय है।

आप क्या बदलाव करने जा रहे हैं और आप किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे?
रॉयल एनफील्ड पिछले 10 वर्षों के दौरान साल दर साल 25 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है और वह काफी हद तक एक देश एक उत्पाद की रणनीति पर आगे बढ़ी। अब हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे विभिन्न देशों और विभिन्न उत्पादों के साथ किस प्रकार विविधीकृत कर सकते हैं। हम ग्रामीण बाजार पर भी काफी ध्यान दे रहे हैं। पिछले छह महीनों के दौरान हमने 500 स्टूडियो स्टोर खोले हैं और वे सभी शहरों के बाहर हैं। हरेक स्टूडियो स्टोर 12 से 13 बाइक प्रति महीने की बिक्री करता है। इन स्टूडियो स्टोरों के खुलने के बाद बुलेट की बिक्री लगभग दोगुनी हो चुकी है। आज 90 फीसदी राजस्व भारत में उत्पादों की बिक्री और एक या दो मॉडलों से आता है। दीर्घावधि में हम आफ्टरसेल मार्केट से 20 से 25 फीसदी और बाहर से 20 से 25 फीसदी राजस्व हासिल करना चाहते हैं।

क्या आप विदेश में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेंगे?
हां, लेकिन बड़े संयंत्र नहीं। वे कंप्लीटरी नॉक्ड डाउन (सीकेडी) जैसे संयंत्र होंगे जिसकी लागत 10 से 20 लाख डॉलर होगी।

उद्योग में क्षमता इस्तेमाल 2008 के बाद सबसे निचले स्तर पर

अभिषेक वाघमारे और अमृता पिल्लई
नई दिल्ली, 5 दिसंबर

भारत के विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता इस्तेमाल साल 2008 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। सितंबर तिमाही में यह 68.9 फीसदी रह गया। दो तिमाही पहले (मार्च 2019) यह 6 साल के उच्चस्तर 76 फीसदी पर पहुंच गया था। गुरुवार को जारी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के बयान में ये बाते कही गई हैं।

नोटबंदी के बाद जनवरी-मार्च 2019 में क्षमता इस्तेमाल धीरे-धीरे सुधरकर 76.1 फीसदी पर पहुंच गया था। मौद्रिक नीति समिति के बयान में कहा गया है, विनिर्माण गतिविधियों में नरमी से 2019-20 की दूसरी तिमाही में क्षमता इस्तेमाल घटकर 68.9 फीसदी पर आ जाने के तौर पर प्रतिबिंबित हुई, जो पहली तिमाही में 73.6 फीसदी रही थी। ये चीजें भारतीय रिजर्व बैंक के ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री और क्षमता इस्तेमाल के सर्वेक्षण में सामने आई।

ये आंकड़े उद्योग की मौजूदा मंदी की गंभीरता बताते हैं। 73.6 फीसदी से घटकर 68.9 फीसदी पर आना, यानी इसमें 4.7 फीसदी की तीव्र गिरावट भी अप्रत्याशित है। यहां तक कि सीजन के लिहाज से समायोजित क्षमता इस्तेमाल 69.8 फीसदी है।

यह संकेत देता है कि जब भी यहां से मांग जोर पकड़ेगी, कंपनियां नई क्षमता पर निवेश से पहले क्षमता इस्तेमाल में सुधार लाएंगी। उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा कि वे वास्तव में क्षमता इस्तेमाल में बड़ी गिरावट देख रहे हैं, हालांकि कुछ क्षेत्र कुल क्षमता इस्तेमाल में और गिरावट को रोकता दिख रहा है।

सीमेंट एक अहम औद्योगिक क्षेत्र है, जो निर्माण व बुनियादी ढांचा क्षेत्र का संकेतक है, चाहे वह सड़क हो, राजमार्ग हो या फिर मेट्रो परियोजनाएं। भारत की सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक अल्ट्राटेक का क्षमता इस्तेमाल दूसरी तिमाही में घटकर 62 फीसदी रह गया,जो पहली तिमाही में 73 फीसदी रहा था। कंपनी ने यह जानकारी दी।

डालमिया भारत के प्रबंध निदेशक और सीईओ और सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सिंघी ने कहा, सीमेंट की मांग में पिछले आठ महीने में नकारात्मकता रही है। उन्होंने कहा, शायद पहली बार सीमेंट की मांग ग्रामीण इलाके में वित्त वर्ष 2020 की पहली छमाही में घटा है। यह बड़ी चिंता का विषय है।

डालमिया भारत की क्षमता का इस्तेमाल 72 फीसदी को छू गया है। विशेषज्ञों ने कहा कि सीमेंट क्षेत्र ने साल की शुरुआत 80 फीसदी क्षमता इस्तेमाल के साथ की थी और उनका अनुमान है कि इस वित्त वर्ष की समाप्ति 67 फीसदी के आसपास होगी। ये चीजें विनिर्माण क्षेत्र के क्षमता इस्तेमाल के बारे में बताती है।

थर्मेक्स के प्रबंध निदेशक व सीईओ एम एस उन्नीकृष्णन ने कहा, पूंजीगत सामान क्षेत्र में क्षमता इस्तेमाल 50 से 65 फीसदी के दायरे में रहा है। सामान्य तौर पर इसे 80 फीसदी होना चाहिए था। हमें उम्मीद है कि तीसरी तिमाही खराब होगी और चौथी तिमाही में स्थिति सुधरेगी।

जिंदल स्टील ऐंड पावर ने हालांकि कहा कि सितंबर तिमाही में क्षमता इस्तेमाल 85 फीसदी रहा और मौजूदा तिमाही में यह बढ़कर 100 फीसदी पर पहुंच गया है। ये बातें जेएसपीएल के प्रबंध निदेशक वी आर शर्मा ने कही।

सितंबर तिमाही में जीडीपी की बढ़त की रफ्तार 26 साल के निचले स्तर 4,5 फीसदी पर आ गई। मौद्रिक नीति समिति ने कहा, इसकी एक अहम वजह सरकार की तरफ से सार्वजनिक खर्च में उछाल है।

वैश्विक आर्थिक संकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जब साल 2008 में झटका दिया था तब आरबीआई ने विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता के इस्तेमाल का सर्वेक्षण शुरू किया था। 2008-09 की पहली तिमाही में क्षमता इस्तेमाल 73.7 फीसदी थी, जो 2009-10 में 80 फीसदी के पार निकल गया था।

क्षमता इस्तेमाल का लेखाजोखा

- सितंबर तिमाही में क्षमता इस्तेमाल 68.9 फीसदी रह गया, जो दो तिमाही पहले (मार्च 2019) 6 साल के उच्चस्तर 76 फीसदी पर पहुंच गया था
- ये आंकड़े उद्योग की मौजूदा मंदी की गंभीरता बताते हैं
- यह संकेत देता है कि जब भी यहां से मांग जोर पकड़ेगी, कंपनियां नई क्षमता पर निवेश से पहले क्षमता इस्तेमाल में सुधार लाएंगी
- भारत की सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक अल्ट्राटेक का क्षमता इस्तेमाल दूसरी तिमाही में घटकर 62 फीसदी रह गया,जो पहली तिमाही में 73 फीसदी रहा था

पांच साल परिचालन के बाद भुगतान बैंक बन सकेंगे एसएफबी

एसएफबी में तब्दील होने वाले सहकारी बैंकों के लिए शुरू में 100 करोड़ रुपये की निवेश पूंजी की जरूरत होगी जिसे व्यवसाय शुरू होने की तारीख से पांच साल के अंदर बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये किया जाएगा

निधि राय
मुंबई, 5 दिसंबर

लघु वित्त बैंक (एसएफबी) के लाइसेंस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नए मसौदा दिशा-निर्देशों में भुगतान बैंकों को पांच साल का परिचालन पूरा करने के बाद एसएफबी में तब्दील होने की अनुमति दी गई है। यदि किसी भुगतान बैंक का प्रवर्तक एसएफबी भी स्थापित करना चाहता है तो दोनों बैंकों को नॉन-ऑपरेटिव फाइनैंशियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) ढांचे के तहत लाया जाएगा।

आरबीआई के दिशा-निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एसएफबी को परिचालन की शुरुआत के तुरंत बाद बैंक का दर्जा दे दिया जाएगा और और उन्हें परिचालन शुरू करने की तारीख से शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाएगी।

आरबीआई ने कहा है, 'लघु वित्त बैंकों के परिचालन में किसी तरह की कोई सीमा या पाबंदी नहीं होगी, हालांकि तरजीह उन आवेदकों को दी जाएगी तो शुरू में देश के पूर्वोत्तर, पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में कम बैंकिंग सुविधा वाले इलाकों में बैंक खोलना चाहेंगे। उम्मीद की जा रही है कि छोटे वित्तीय बैंक शुरू में स्थानीय जरूरतें पूरी करेंगे। पांच साल की शुरुआती अवधि के बाद, और उनकी समीक्षा के बाद आरबीआई लघु वित्त बैंकों की गतिविधियों का दायरा बढ़ा सकता है।'

दिशा-निर्देशों में कहा गया है, 'हालांकि एनबीएफसी/एमएफआई/पीबी की शाखाओं को परिचालन शुरू होने या विलय/बंद होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अंदर बैंक शाखाओं में तब्दील किया जाएगा। एसएफबी और एनबीएफसी/एमएफआई एक साथ परिचालन नहीं कर सकेंगे।'

एयू स्मॉल फाइनैंस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी संजय अग्रवाल ने निर्णायक मसौदे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, 'हम इन दिशा-निर्देशों का स्वागत करते हैं। वे प्रगतिशील प्रवृत्ति के हैं और भुगतान बैंकों को एसएफबी में तब्दील करना एक अच्छा निर्णय है। हम शुरुआती अनुभव का हिस्सा बनकर उत्साहित हैं और यह साबित करने में सक्षम हैं कि यह मॉडल मजबूत था। हम इसे लेकर उत्साहित हैं कि नई मिसाल कायम करने में सक्षम रहे हैं।'

अपने दिशा-निर्देशों में आरबीआई ने कहा है कि स्वेच्छा से एसएफबी में तब्दील होने वाले सहकारी बैंकों के लिए शुरू में 100 करोड़ रुपये की निवेश पूंजी की जरूरत होगी जिसे व्यवसाय शुरू होने की तारीख से पांच साल के अंदर बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये किया जाएगा।

हालांकि रेटिंग एजेंसी इक्रा इस कदम को बाधा के तौर पर नहीं देख रही है। इक्रा के समूह प्रमुख (वित्तीय क्षेत्र की रेटिंग) कार्तिक श्रीनिवासन ने कहा, 'आरबीआई ने आवेदक के लिए निवेश पूंजी की शर्त को पहले के 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया है। लेकिन हमारे नजरिये से इसे एक बाधक कारक के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि कई मौजूदा एसएफबी ने बड़ी पूंजी के साथ परिचालन शुरू किया है।'

स्मॉल फाइनैंस बैंक में तब्दील होने का मौका

- आरबीआई के दिशा-निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एसएफबी को परिचालन की शुरुआत के तुरंत बाद बैंक का दर्जा दे दिया जाएगा
- उन्हें परिचालन शुरू करने की तारीख से शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाएगी
- अगर किसी भुगतान बैंक का प्रवर्तक एसएफबी भी स्थापित करना चाहता है तो दोनों बैंकों को नॉन-ऑपरेटिव फाइनैंशियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) ढांचे के तहत लाया जाएगा

शहरी सहकारी बैंकों के लिए नियम होंगे सख्त

व्यवस्था में बड़ी उधारी पर सूचना साझा करेगा शहरी सहकारी बैंक

अभिजित लेले
मुंबई, 5 दिसंबर

पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में हुई धोखाधड़ी से संकेत लेते हुए भारतीय रिजर्व बैंक शहरी सहकारी बैंकों के लिए एकल व समूह उधारी के नियमों में संशोधन करेगा। आरबीआई 500 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा परिसंपत्ति वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए बड़े क्रेडिट पर सूचना साझा करना जरूरी बनाएगा।

आरबीआई ने कहा कि वह शहरी सहकारी बैंकों के नियामकीय दिशानिर्देश में संशोधन करेगा ताकि उधारी, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उधारी में संकेंद्रित जोखिम घटाया जा सके और वित्तीय समावेशन में उनकी भूमिका मजबूत बनाई जा सके।

इंडियन बैंक एसोसिशन के चेयरमैन और भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा, शहरी सहकारी बैंकों के लिए नियामकीय कदमों से इन संस्थानों पर आम लोगों का भरोसा बढ़ेगा। आरबीआई ने कहा, इन कदमों से शहरी सहकारी बैंकों में मजबूती आएगी और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा होगी। संशोधित नियमों के अनुपालन के लिए वह समयसीमा बताएगा और जल्द ही प्रस्तावित बदलाव से संबंधित मसौदा जारी करेगा।

> पीएमसी बैंक के फॉरेंसिक ऑडिट की अंतिम रिपोर्ट इस महीने के आखिर तक मिल सकती है

भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों के लिए सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (सीआरआईएलसी) गठित किया है ताकि वित्तीय दबाव का जल्द पता लग सके और मजबूती से निगरानी हो। 500 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा परिसंपत्ति वाले शहरी सहकारी बैंकों को सीआरआईएलसी के दायरे में लाने का फैसला लिया गया है ताकि ऐसे सहकारी बैंकों की तरफ से दी गई बड़ी उधारी का डेटाबेस तैयार हो सके। इस संबंध में विस्तृत निर्देश 31 दिसंबर 2019 को जारी किए जाएंगे।

आरबीआई के निदेशक और सहकारी बैंक के विशेषज्ञ सतीश मराठे ने कहा, शहरी सहकारी बैंकों के पास वाणिज्यिक बैंकों की तरफ से बड़े देनदारों से संबंधित जानकारी नहीं होती। सीआरआईएलआईसी से और सूचना मिलने पर उन्हें फैसला लेने में मदद मिलेगी। साथ ही इस कदम से एकल व समूह उधारी की सीमा तय होगी। सीमा में कमी से जोखिम घटेगा।

साइबर सुरक्षा जोखिम को लेकर शहरी सहकारी बैंकों को सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार करेगा।

पीएमसी बैंक

पीएमसी बैंक का फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है और इसकी अंतिम रिपोर्ट इस महीने के आखिर तक मिल सकती है। यह कहना है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का। इसके साथ ही पीएमसी बैंक प्रोफेशनल मूल्यांकनकर्ता की मदद से परिसंपत्ति का मूल्यांकन करेगा, जिसे कंपनियों ने कर्ज लेने के लिए जमानत के तौर पर रखा है और उन संपत्तियों का भी मूल्यांकन किया जाएगा जिसकी पहचान मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा व प्रवर्तन निदेशालय ने की है।

फर्मों की आय के लिए रहेंगी मुश्किलें

हंसिनी कार्तिक
मुंबई, 5 दिसंबर

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को जब रीपो दरों में कटौती नहीं करने का रुख अपनाया तो बाजार में गिरावट आई। हालांकि बीएसई सेंसेक्स बहुत ज्यादा नहीं टूटा और 40,779 अंक के स्तर पर करीब-करीब स्थिर बंद हुआ।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के प्रमुख पंकज पांडे ने कहा, मौद्रिक नीति में महंगाई बढ़ने के अनुमान को कुछ हद तक समाहित किया जा चुका था। प्रभुदास लीलाधर के मुख्य पोर्टफोलियो मैनेजर अजय बोडके ने कहा, भविष्य में अगर जरूरत हुई तो मौद्रिक नीति समिति ब्याज दरें घटाने का इच्छुक होगा, इससे कुछ उम्मीद जगी। लेकिन भारतीय कंपनी जगत के लिए इसमें समस्या छुपी हुई है। प्रमुख नकारात्मक चीज है क्षमता इस्तेमाल, जो पिछले एक साल में 74 फीसदी से घटकर 68 फीसदी रह गया है। आलोचक कहते हैं कि निर्यात मांग और स्थानीय विनिर्माण सुस्त बना हुआ है। सेवा क्षेत्र की गतिविधियां, ग्रामीण उपभोग और वाहन की सुस्त मांग इस समस्या को और बढ़ा रहा है। यह बताता है कि आरबीआई ने वैश्विक रेटिंग एजेंसियों की तरह वित्त वर्ष 2020 के लिए जीडीपी की रफ्तार का अनुमान 5.5 फीसदी से घटाकर 4.9 फीसदी कर दिया। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि कंपनियां मानकर लचे कि मंदी लंबे समय तक रहेगी, जिसमें सुधार में एक साल या ज्यादा वक्त लग सकता है, ऐसे में आय की रफ्तार भी सुस्त बनी रहेगी।

इक्विटी के लिए इसका मतलब यह भी है कि अगला सकारात्मक संकेत आम बजट से मिलेगा। बोडके ने कहा, तब तक बाजार अस्थिर या सीमित दायरे में बना रह सकता है। उन्होंने कहा, बजट में उपभोग में मजबूती को लेकर घोषणा मसलन व्यक्तिगत आयकर की दर, पूंजीगत लाभ कर या लाभांश वितरण कर में नरमी से सेंटिमेंट सुधरेगा और शायद देश में उपभोक्ताओं की तरफ से खर्च में सुधार करेगा।

इन चीजों में बदलाव हो सकता है, अगर बैंक रीपो दरों में कटौती का फायदा मौजूदा रफ्तार के मुकाबले तेजी से देना शुरू कर दे। इस पर नजर डालिये : आरबीआई ने फरवरी से अब तक रीपो दरों में 135 आधार अंकों की कटौती की है, लेकिन बैंकों की उधारी दर इस अवधि में 49 आधार अंक घटी है। बैंक अक्सर कहते हैं कि छोटी बचत दर, जमा दरों में कटौती के लिहाज से अवरोधकारी है। छोटी बचत दर 6.9 से 8.6 फीसदी तक है, जो बैंक जमा दर से 100-120 आधार अंक ज्यादा है। बैंक हालांकि इस अवधि में जमा दरों में 47 आधार अंकों की कटौती कर चुके हैं, लेकिन इसमें कमी चरणबद्ध तरीके से नहीं हुई है।

पांडे ने कहा कि उधारी की लागत स्थिर होने के साथ बैंकों के पास बढ़त की गुंजाइश है, जो बढ़त को लेकर ठोस फैसले लेने में सहायता करेगा।

उपभोक्ताओं के खर्च व होमलोन की क्षमता की जांच तब होगी जब रकम सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी। सितंबर तिमाही के नतीजे का रुख बताता है कि बैंक अब खुदरा कर्ज को लेकर भी सतर्क हो गए हैं, जो डिस्क्रिशनरी गुड्स की मांग बढ़ाने के लिए अहम है। बैंकरों ने कहा कि त्योहारी सीजन में मांग उत्साहजनक रही है।

ब्याज घटाने वाले 26 वैश्विक केंद्रीय बैंकों में शुमार आरबीआई

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 5 दिसंबर

गुरुवार को रीपो दर को 5.15 प्रतिशत पर बनाए रखने और अर्थशास्त्रियों तथा बाजार को चौंकाने के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) 31 में से 26 वैश्विक केंद्रीय बैंकों में शामिल है जो दर कटौती की होड़ में शामिल रहे हैं। स्वीडन, ब्रिटेन, नॉर्वे, कनाडा और चेक रिपब्लिक में शेष पांच केंद्रीय बैंकों ने अपनी प्रमुख दरों में इजाफा किया है। कैलेंडर वर्ष 2019 में अब तक आरबीआई रीपो दर को 135 आधार अंक तक की कटौती कर 5.15 प्रतिशत पर ला चुका है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैठक के बाद रिवर्स रीपो दर भी 4.90 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी रही और मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 5.4 प्रतिशत पर है। आरबीआई द्वारा दरों को लेकर अपना रुख स्पष्ट किए जाने के बाद अब ध्यान अमेरिका के फेडरल रिजर्व की दो-दिवसीय नीतिगत बैठक पर केंद्रित हो गया है जो 11 दिसंबर से शुरू हो रही है। अक्टूबर के अंत में केंद्रीय बैंक ने अपनी प्रमुख उधारी दर 25 आधार अंक तक घटाकर 1.5-1.75 प्रतिशत के दायरे में कर दी और 2019 में उसकी यह तीसरी कटौती थी।

राबोबैंक इंटरनैशनल में वरिष्ठ अमेरिकी रणनीतिकार फिलिप मरे ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में लिखा है, 'जहां हमें अब 2020 की दूसरी छमाही में कमजोर जीडीपी वृद्धि का अनुमान है, लेकिन फेडरल फंड की दर के लिए लक्षित रेंज को घटाकर शून्य किया जाना अर्थव्यवस्था में उछाल के लिहाज से पर्याप्त नहीं हो सकता।'

बीएस बातचीत

हर बार रीपो दर नहीं घटा सकता भारतीय रिजर्व बैंक

पांचवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैठक के बाद आरबीआई के गवर्नर **शक्तिकांत दास** ने मीडिया के साथ बातचीत में दर कटौती, ब्याज दरों की स्थिति, एनबीएफसी क्षेत्र के बारे में विस्तार से बातचीत की। पेश हैं उनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश:

मुद्रास्फीति में गिरावट आने और जुलाई तक इसके 3.8 से 4 प्रतिशत के दायरे में रहने की उम्मीद के बीच आपने दरों में कटौती क्यों नहीं की? आप बजट से क्या उम्मीद करेंगे और क्या फरवरी में दर घटाएंगे?

मौजूदा समय में खासकर खाने-पीने की मुद्रास्फीति में मौजूदा तेजी पर विचार करने की जरूरत है। हमारी गणना से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति ऊंची बनी रहेगी, और इसमें नरमी कई कारकों पर आधारित है। मुख्य मुद्रास्फीति मौजूदा दायरे में बनी रहने का अनुमान है, लेकिन दूरसंचार से संबंधित कारक हैं जो इस पर कुछ प्रभाव डाल सकते हैं। एमपीसी इस पर स्थिति स्पष्ट करना चाहेगी। मुद्रास्फीति का सही लक्ष्य निर्धारित करना आरबीआई का मुख्य उद्देश्य है और इसके लिए उसे वृद्धि के लक्ष्य को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। एमपीसी ने स्पष्ट कहा है कि आगे और दर कटौती की गुंजाइश है तथा आरबीआई स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरबीआई कदम उठाएगा। हम वृद्धि के संबंध में कुछ खास सकारात्मक बदलाव देख रहे हैं, लेकिन इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी है, क्योंकि यह देखना जरूरी है कि हालात कैसे रहेंगे। जहां तक बजट का सवाल है तो यह चिंता का सवाल है कि राजकोषीय घाटा अधिक होगा। हम स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आरबीआई ने भी उसके बाद दरें घटाई हैं और पर्याप्त तरलता की स्थिति है। दर कटौती का पूरा असर दिख भी रहा है। इसका असर पूरी तरह दिखने में कुछ और समय लगेगा। इसलिए एमपीसी ने दर कटौती को अस्थायी रूप से टालने का निर्णय लिया।

क्या एमपीसी फिलहाल वृद्धि के पक्ष में कदम उठा सकती है?

मैं इस बिंदु पर बहस नहीं करूंगा। लेकिन दर कटौती का समय 135 आधार अंक की कटौती के असर को समझने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इसका असर दिखने दीजिए जिससे कि हम ज्यादा लाभ मुहैया करा सकें। हम हर अवसर पर दर कटौती का सिलसिला बरकरार नहीं रख सकते।

सरकार राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर थक चुकी है और राजस्व वृद्धि धीमी होने से वृद्धि को मदद मिलने की पर्याप्त गुंजाइश नहीं रह गई है। आरबीआई और आप बजट का इंतजार कर रहे हैं। वृद्धि की जिम्मेदारी कौन लेगा?

यह जिम्मेदारी दोनों की है और हम तालमेल के साथ इस दिशा में कार्य बरकरार रखेंगे। आपका यह कहना गलत है कि हम इसके लिए एक-दूसरे की ओर देख रहे हैं। वृद्धि एक राष्ट्रीय मुद्दा है। दूसरी और तीसरी तिमाही हमेशा से ऊंचे राजकोषीय घाटे से जुड़ी रही है, क्योंकि राजस्व प्रवाह चौथी तिमाही में बढ़ता है और अन्य कर संग्रह, तथा अन्य खर्च पूरे वर्ष समान रूप से संतुलित रहते हैं। वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकार के कदमों पर विचार करने के बाद हमें स्पष्ट स्थिति देखने को मिलेगी।

क्या जीडीपी वृद्धि दर में कमी के साथ रोजगार नुकसान की आशंका है?

दो महीने के अंतराल के साथ किए गए अपने सर्वेक्षणों के आधार पर हमें अगले वर्ष की दूसरी छमाही में आय वृद्धि में सुधार की उम्मीद है।

नीतिगत बयान काफी हद तक आपके द्वारा उठाए गए कदमों से जुड़ा हुआ है, और संकटग्रस्त एनबीएफसी को एनसीएलटी में लाना नियामक का काम है। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

नियामक के तौर पर, आरबीआई की जिम्मेदारी संकटग्रस्त एनबीएफसी को एनसीएलटी के पास भेजने के साथ समाप्त हो जाती है। उसके बाद, इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और लेनदारों की समिति (सीओसी), और फिर एनसीएलटी को जिम्मेदारी निभानी होती है। इसलिए, हमारा लक्ष्य सिर्फ हालात का विश्लेषण करना और उसका रिकॉर्ड तैयार करना है। हमें पूरी स्थिति व्यावहारिक तौर पर देखने की जरूरत है। हम व्यवस्था में ज्यादा व्यवधान और अनिश्चितता पैदा नहीं कर सकते।

महंगाई से थमे आरबीआई के कदम

पृष्ठ-1 का शेष

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, 'मुख्य मुद्रास्फीति में मौजूदा तेजी खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने की वजह से आई है। हमारा गणित कहता है कि वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में यह उच्च स्तर पर बना रहेगा। लेकिन फरवरी के बाद इसमें नरमी आनी शुरू हो सकती है।' अर्थशास्त्रियों और बाजार को पूरी उम्मीद थी विकास दर में तेजी के लिए दर में कटौती की जाएगी। आरबीआई के निर्णय से 10 वर्षीय बॉन्ड का प्रतिफल 15 आधार अंक चढ़कर 6.61 फीसदी पर बंद हुआ।

डीबीएस समूह के मुख्य अर्थशास्त्री तैमूर बेग ने कहा, 'पिछली बार आरबीआई ने इस तरह से कब चकित किया था, यह मुझे याद नहीं है। अब तक वह विकास दर को बढ़ावा देने को लेकर ज्यादा सक्रियता दिखाता रहा है। हालांकि इस बार उसने बाजार की उम्मीद को धूमिल कर दिया।' हालांकि केंद्रीय बैंक ने भरोसा दिया कि जब तक दरों में कटौती की गुंजाइश होगी और जब कभी इसकी जरूरत होगी, हम समायोजित रुख जारी रखेंगे। ऐसी संभावना है कि नरमी को दूर करने के लिए सरकार कुछ और वित्तीय तथा अन्य उपाय कर सकती है। आरबीआई दरों में कटौती से पहले आम बजट से भी संकेत लेना चाह रहा है।आरबीआई गवर्नर ने कहा, 'इस महत्त्वपूर्ण घड़ी में बेहतर नीतजे के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीति को समन्वय के साथ काम करना सबसे जरूरी है।' आरबीआई ने फरवरी से अब तक पांच बार में रीपो दर में कुल 135 आधार अंक की कटौती की है। अब मौद्रिक नीति समिति इन कदमों के असर को देखना चाहती है।आईडीएफसी एएमसी में फिक्स्ड इनकम के प्रमुख सुयश चौधरी ने कहा, 'आरबीआई का यह कदम हमारे लिए चकित करने वाला रहा।' उन्होंने कहा कि नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2016 के मध्य से 2018 के मध्य तक 11-12 फीसदी से घटकर 6 फीसदी रह गई है। पूरे साल के लिए यह 7 से 8 फीसदी रह सकता है।दास ने कहा कि जहां तक दरों में कटौती का लाभ देने की बात है तो मनी मार्केट के मामले में यह पूरी तरह से किया गया है लेकिन अैंकों ने अभी तक अपने ग्राहकों को इसका पूरा लाभ नहीं दिया है। रुपये में ताजा कर्ज में औसतन 44 आधार अंक की गिरावट आई है। इसका लाभ धीरे-धीरे बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिया जा रहा है।

भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा, 'दरों को यथावत रखने का आरबीआई का निर्णय चकित करने वाला रहा, लेकिन उचित है।' हालांकि उन्होंने दरों में कटौती का कोई भरोसा नहीं दिया। आरबीआई ने कहा कि वह वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी में सुविधा प्रदान करने के लिए 10,000 रुपये तक की सीमा वाला एक नया प्री-पेड कार्ड लाएगा।

संक्षेप में

बीपीएसएल के सिंघल की याचिका खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने कथित बैंक कर्ज घोटाले से जुड़े करोड़ों रुपये के धनशोधन मामले में गुरुवार को भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर कर दी। प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष न्यायाधीश भरत पराशर को बताया कि आरोपी ने अतीत में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है और अगर उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति दी गई तो गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं। *भाषा*

इंदौर से दिल्ली, अहमदाबाद बेंगलूरु पहुंचाएगी गोएयर

निजी एयरलाइन कंपनी गोएयर ने गुरुवार को घोषणा की कि वह इंदौर को दिल्ली, अहमदाबाद और बेंगलुरू से जोड़ने के लिए 20 दिसंबर से दैनिक उड़ानें शुरू करेगी। गोएयर के एक अधिकारी ने यहां बताया कि वाडिया समूह की कंपनी 20 दिसंबर से इंदौर- दिल्ली, दिल्ली-इंदौर, इंदौर-अहमदाबाद, अहमदाबाद-इंदौर और बेंगलुरू-इंदौर मार्गों पर एक-एक उड़ान हर रोज के लिए शुरू करेगी। *भाषा*

राज्यों के साथ कर बंटवारा यथावत

अरूप रॉयचौधरी
नई दिल्ली, 5 दिसंबर

केंद्र व राज्यों के बीच कर बंटवारे के मामले में माना जा रहा है कि 15वें वित्त आयोग ने यथास्थिति बरकरार रखी है और 2020-21 के लिए मौजूदा 42 प्रतिशत के स्तर को बरकरार रखा है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दी है और राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशों से अवगत कराया है।

एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि वित्त आयोग फिलहाल राज्यों को बंटवारे के प्रतिशत को यथावत रखा है। आयोग अतिरिक्त समय का इस्तेमाल आर्थिक मंदी, केंद्र और राज्यों के अवास्तविक राजकोषीय व वित्तीय लक्ष्यों से निपटने और दिल्ली और पुदुच्चेरी जैसे अन्य केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना में जम्मू कश्मीर की स्थिति पर विचार करने के लिए करेगा और अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 2020 में सौंपेगा।

राष्ट्रपति अब अंतरिम रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय को सौंपेंगे और इसके आधार पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम के अधिकारी इसके आधार पर 2020-21 का बजट तैयार करने में सक्षम हो सकेंगे। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अंतरिम रिपोर्ट बजट के महज एक दिन पहले सार्वजनिक की जा सकती है, जब इसे संसद के पटल पर रखा जाएगा।

पिछले महीने के आखिर में मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 11 महीने बढ़ा दिया था। आयोग वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए अपनी पूर्ण रिपोर्ट पेश करेगा। इस तरह से 15वें वित्त आयोग को 6 वित्त वर्षों के लिए अपनी रिपोर्ट देनी होगी, जो सामान्यतया 5 साल होती है। बहरहाल यह भारत के संविधान के प्रावधानों के विपरीत नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 280 में प्रावधान है कि वित्त आयोग का कार्यकाल 5 साल या राष्ट्रपति के द्वारा तय अवधि के मुताबिक होगा। सामान्य शब्दों में कहें तो इसका मतलब यह है कि 15वां वित्त आयोग दो रिपोर्टों के माध्यम से 6 साल के लिए सिफारिश कर सकता है, जब 16वें वितत्त आयोग का गठन होगा तो वह 2025-26 से 2029-30 के लिए कर के बंटवारे पर विचार करेगा, न कि 2026-27 से। इसकी वजह से 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 5 साल रहेगा।

15वें वित्त आयोग को अतिरिक्त समय नए केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर विचार करने के लिए दिया गया है।

जम्मू कश्मीर का मसला यह है कि तकनीकी रूप से जहां केंद्र शासित प्रदेशों को बंटवारे वाले कर पूल में हिस्सा नहीं मिलता है और उनके संसाधन केंद्र के हिस्से से आते हैं, वहीं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि 15वां वत्ति आयोग जम्मू कश्मीर के मामले में बंटवारे वाले पूल से हिस्सेदारी देने पर विचार करेगा, यानी उसे राज्य के रूप में देखा जाएगा।

राष्ट्रपति को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी

- वित्त मंत्रालय अब वित्त वर्ष 21 का बजट तैयार करने में करेगा रिपोर्ट का उपयोग
- बजट की तारीख के आसपास अंतरिम रिपोर्ट की जा सकती है सार्वजनिक
- अधिकारियों ने कहा कि अंतरिम रिपोर्ट में यथास्थिति बकरार
- आर्थिक मंदी को देखते हुए तैयार होगी 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट

60 करोड़ डॉलर निवेश करेगा कनाडा पेंशन बोर्ड

राघवेंद्र कामत
मुंबई, 5 दिसंबर

कनाडा का सबसे बड़ा पेंशन फंड प्रबंधक कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड (सीपीपीआईबी) ने आज कहा है कि वह एनआईआईएफ मास्टर फंड के माध्यम से 60 करोड़ डॉलर निवेश करेगा। यह नैशनल इन्वेस्टमेंटमेंट ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) के तहत आता है। इस समझौते में एनआईआईएफ मास्टर फंड में 15 करोड़ डॉलर निवेश और 45 अरब डॉलर एनआईआईएफ मास्टर फंड के साथ भविष्य में निवेश की संभावनाओं के सह निवेश का अधिकार शामिल है।

आएगा धन

सीपीपीआईबी के निवेश के साथ एनआईआईएफ मास्टर फंड के पास अब 2.1 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताएं हैं और इसने फंड के आकार का शुरुआती लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसके साथ ही एनआईआईएफ मास्टर फंड निवेशकों को 3 अरब डॉलर के सह निवेश का अधिकार है, जिससे एनआईआईएफ मास्टर फंड भारत की बड़ी बुनियादी ढांचा जरूरतों में निवेश में सक्षम हो सकेगा।

एनआईआईएफ मास्टर फंड प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में इक्विटी पूंजी का निवेश करता है, जिसका ध्यान परिवहन, ऊर्जा और शहरी बुनियादी ढांचे पर है।

सीपीपीआईबी भी अब एनआईआईएफ मास्टर फंड निवेशकों में शामिल हो गया है, जिसमें अबूधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ऑस्ट्रेलियन सुपर, ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान, टेमासेक, ऐक्सिस बैंक, एचडीएफसी ग्रुप, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने निवेश किया है।

बजट में एटीएफ, प्राकृतिक गैस आ सकते हैं जीएसटी में

भाषा
नई दिल्ली, 5 दिसंबर

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि उन्हें आगामी बजट में विमानन ईंधन (एटीएफ) और प्राकृतिक गैस को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाए जाने की दिशा में पहल किए जाने की उम्मीद है।

प्रधान ने यहां फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा कि उन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद है कि वह करों के दोहराव को कम करने तथा कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के लिए एटीएफ और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने के बारे में आगामी बजट में कोई पहल किए जाने का संकेत देंगी। प्रधान लंबे समय से एटीएफ और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने की पैरवी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि देश में प्राकृतिक गैस की मांग अगले 10 साल में तीन गुना से अधिक बढ़ाकर देश की कुल ईंधन मांग के 15 प्रतिशत पर पहुंच सकती है और इसकी पूर्ति के लिए गैस की बुनियादी संरचना पर 60 अरब डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'अभी गैस की खपत 16.60 करोड़ घनमीटर प्रतिदिन है। कुल ईंधन मांग में इसकी हिस्सेदारी 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य पाने के लिए खपत को बढ़ाकर प्रतिदिन 60 करोड़ घनमीटर करने की जरूरत है।'

उन्होंने कहा कि खपत के मौजूदा स्तर में घरेलू उत्पादन की आठ से नौ करोड़ घनमीटर की हिस्सेदारी है और शेष की पूर्ति आयात के जरिए की जाती है। प्रधान ने कहा कि एलएनजी आयात टर्मिनल बनाने, पाइपलाइन बिछाने और शहरी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार करने में निवेश किया जा रहा है, ताकि देश में कम प्रदूषण करने वाले ईंधनों की खपत बढ़ाई जा सके।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गैस के दो फायदे हैं। यह तरल ईंधनों की तुलना में सस्ता है और प्रदूषण भी कम करता है। इसकी खपत बढ़ने से भारत को कम कार्बन उत्सर्जन वाले भविष्य की ओर बढ़ने में मदद मिल सकती है।

संसद की कैंटीन में सब्सिडी छोड़ने को सांसद राजी

सांसदों ने संसद की कैंटीन में खाद्य वस्तुओं पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ने का सर्वानुमति से निर्णय किया है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सुझाव के बाद किया। इनका मानना है कि इतना अधिक सब्सिडी देना उपयुक्त नहीं है। उन्होंने बताया कि सब्सिडी समाप्त होने से सालाना 17 करोड़ रुपये बचाया जा सकेगा। यह निर्णय लागू होने के बाद खाद्य पदार्थों की कीमतें लगभग दोगुनी हो जाएगी। गौरतलब है कि संसद भवन के कैंटीन में सब्सिडी लंबे समय से विवादास्पद मुद्दा रहा है और कुछ वर्ष पहले इसमें कटौती की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष के साथ बैठक के बाद कार्य मंत्रणा समिति में विभिन्न दलों के नेताओं ने सब्सिडी समाप्त करने के संबंध में निर्णय किया। भाजपा नेता और कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य राजीव प्रताप रूडी ने कहा, 'स्पीकर की पहल पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया।' *भाषा*

पीएनबी ने चुना जवाब न देने का विकल्प

पवन लाल
नई दिल्ली, 5 दिसंबर

भले ही बड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को सरकार ने गुरुवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है और वह विजय माल्या के बाद इस तरह के दूसरे भारतीय बन गए हैं, लेकिन पिछले साल हुए करोड़ों रुपये के पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले की फोरेंसिक जांच से जुड़े लोगों का कहना है कि पहले के अनुमान की तुलना में उधार ली गई कुल राशि कहीं ज्यादा है।

पीएनबी के अधिकारियों ने एलओयू की सही राशि बताने से इनकार किया है, जो मोदी को जारी किए गए। लेकिन अगर बीडीओ इंडिया के साथ साझा किए गए और कब्जे में लिए गए सभी संबंधित दस्तावेजों को देखें तो मोदी द्वारा एक दशक में लिया गया कुल कर्ज बहुत ज्यादा है।

फोरेंसिक जांच से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा, 'पीएनबी द्वारा जरूरी सूचनाओं में से सिर्फ 40 प्रतिशत ही मुहैया कराई गई है। इस हिसाब से कोई सीमा नहीं तय की जा सकती है कि कुल कितने मूल्य का एलओयू जारी किया गया है। संभावित मूल्य किसी निजी या सार्वजनिक अनुमान से ज्यादा हो सकता है, जिसे अब तक साझा किया गया है।'

दरअसल यह धोखाधड़ी लोगों के एक समूह द्वारा की गई, जो लंबे समय से बहुत निकटता से काम कर रहे थे। एलओयू सिर्फ पीएनबी के ब्राडी रोड शाखा से ही जारी नहीं हुए बल्कि अन्य शाखाओं और नजदीकी से जुड़े एक गिरोह, जो एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, ने मिलकर काम किया। उन्होंने कहा, 'यह सोची समझी और जटिल कवायद थी और किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था।'

पिछले एक दशक के दौरान मोदी और उनके सहयोगियों ने कितने पैसे निकाले हैं, यह तय करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसकी वजह यह है कि फोरेंसिक ऑडिट कंपनी बीडीओ इंडिया को पंजाब नैशनल बैंक ने जो डेटा और एलओयू की प्रतियां मुहैया कराई हैं, धोखाधड़ी की पूरी अवधि की लग्जरी आभूषण कारोबार का आईपीओ (आरंभिक सार्वजनिक पेशकश) आने की उम्मीद कर रहे थे, जिन्होंने करीब एक दशक पहले लेटर आफ अंडरटेकिंग (एलओयू) के माध्यम से ट्रायल ऐंड एरर के आधार पर लेना शुरू किया। छोटी राशियों से इसकी शुरुआत हुई और उसका भुगतान हो गया। बहरहाल समय बीतने के साथ यह राशि बड़ी होती गई और मोदी ने आखिरी बार एलओयू से 6800 करोड़ रुपये यानी करीब 1 अरब डॉलर लिए।

नीरव मोदी घोटाला

नीरव मोदी बन गया है विजय माल्या के बाद दूसरे आर्थिक भगोड़ा

150 अवैध एलओयू का इस्तेमाल किया मोदी की कंपनियों ने

6,800 करोड़ रु अंतिम एलओयू का मूल्य

2 ट्रस्ट भी नीरव के परिवार के, जो इस धोखाधड़ी में शामिल

- फोरेंसिक रिपोर्ट में नीरव मोदी-पीएनबी धोखाधड़ी के ज्यादातर आंकड़े नहीं

मुंबई के कर्ज वसूली न्यायाधिकरण में पीएनबी द्वारा दायर कानूनी दस्तावेजों से पता चलता है कि मोदी ने अवैध तरीके से कम से कम 150 एलओयू का इस्तेमाल किया है। यह राशि उनकी फर्मों स्टेलर डॉयमंड, सोलर एक्सपोर्ट और डॉयमंड आर अस द्वारा बराबर के अनुपात में ली गई। ये तीनों कंपनियां समूह की अन्य कंपनियों से जुड़ी थीं, जिनमें फायरस्टार डॉयमंड्स और फायरस्टार डॉयमंड्स इंटरनैशनल प्राइवेट शामिल हैं, जो नीरव मोदी द्वारा चलाए जा रहे जो पारिवारिक ट्रस्टों से जुड़ी हैं। पीएनबी-नीरव मोदी धोखाधड़ी पर अंतिम फोरेंसिक बीडीओ रिपोर्ट पिछले साल मार्च में आई। बहरहाल इस मामले पर नजर रखने वालों ने कहा कि अगर बैंक आगे और जांच का विकल्प चुनता है तो ज्यादा सही आंकड़े हासिल करने के लिए ऐसा किया जा सकता है।

'बाजार ने अच्छे और कम अच्छे एनबीएफसी में किया है फर्क'

सुब्रत पांडा
मुंबई, 5 दिसंबर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि बाजार ने अच्छे और कम अच्छे एनबीएफसी में अंतर किया है और बेहतर प्रदर्शन करने वाले एनबीएफसी को आईएलऐंडएफएस की घटना से पहले की दरों पर पैसा मिल रहा है।

फिलहाल अच्छे एनबीएफसी 3 महीने के वाणिज्यिक पत्र 5-6 फीसदी के ब्याज दर पर जुटा रहे हैं जबकि उनके मुकाबले कम अच्छे एनबीएफसी को 3 महीने के वाणिज्यिक पत्र के लिए करीब 8-9 फीसदी की दर से ब्याज चुकाना पड़ रहा है। वहीं इस श्रेणी में आने वाली कुछ एनबीएफसी को ऋण बाजार या धन बाजार से बिल्कुल भी पैसा नहीं मिल पा रहा है।

इक्रा के उपाध्यक्ष और सेक्टर प्रमुख अनिल गुप्ता ने कहा, 'आईएलऐंडएफएस के दौर से पहले 3 महीने के वाणिज्यिक पत्र के लिए दरों में अंतर 1 फीसदी से कम था और अब यह करीब 3 फीसदी है।'

टाटा कैपिटल के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी राजीव सभरवाल ने कहा, 'एनबीएफसी के लिए रकम की उपलब्धता में सुधार आया है। रकम की लागत कम हुई है (वास्तविक ब्याज दर कम हुए हैं) और लंबी अवधि का वित्त उपलब्ध है। अब वाणिज्यिक पत्र 12 महीनों के लिए जारी किए जा रहे हैं जो पहले 3-6 महीनों के लिए जारी किए जा रहे थे और ऋण पत्र 3-5 साल के लिए मौजूद हैं जो कि 12-18 महीनों के लिए ही थे।'

दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, 'एनबीएफसी क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है और इस क्षेत्र में धीरे धीरे ऋण के प्रवाह में सुधार हो रहा है।' इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छाया बैंकिंग प्रणाली में व्याप्त तरलता की स्थितियों को देखते हुए रिजर्व बैंक जहां कहीं भी जरूरी होगा यह सुनिश्चित करने में संकोच नहीं करेगा कि कोई भी बड़ा या व्यवस्थागत रूप से महत्त्वपूर्ण एनबीएफसी धराशायी नहीं हो।

मुंबई में गुरुवार को मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक के पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास व उनके डिप्टी गवर्नर *पीटीआई*

रिजर्व बैंक लगातार शीर्ष 50 एनबीएफसी पर करीबी और सघनता से नजर बनाए हुए है। गवर्नर ने कहा, 'हमें जहां कहीं भी लग रहा है हम गहराई से उनके बही खातों और अन्य संख्याओं पर नजर रख रहे हैं। हमें पूरी तरह से पता है और मैं कुछ हद तक विश्वास से कह सकता हूं कि हमें अच्छी तरह से समझ है कि संकट कहां पर है और जो एनबीएफसी संकटग्रस्त हैं हम गहनता से उन पर नजर रख रहे हैं।'

बहरहाल, गवर्नर ने कहा कि रिजर्व बैंक संकटग्रस्त एनबीएफसी के प्रबंधन और प्रमोटरों के साथ एक निश्चित अंतराल पर विचार विमर्श करता है।

गवर्नर ने कहा, 'रिजर्व बैंक इन एनबीएफसी के प्रमोटरों के साथ साथ उनके प्रबंधन के साथ भी चर्चा करता है। हम उन्हें स्पष्ट अपने अपेक्षित उपायों के बारे में बताते हैं जो उन्हें अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए उठाने चाहिए।'

आईएलऐंडएफएस की असफलता के बाद एनबीएफसी को बाजार से रकम नहीं मिल पा रहा था और बैंक भी सचेत हो गए थे जिसके बाद वे उन्हें ऋण नहीं दे रहे थे। गवर्नर ने कहा हालांकि, एनबीएफसी को मिलने वाले बैंक ऋण में नवंबर के अंत तक 26.5 फीसदी का इजाफा हुआ है।

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक बैंकों ने गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों को अप्रैल से अक्टूबर 2019 तक 72,136 करोड़ रुपये दिए जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 66,222 करोड़ रुपये दिए गए थे। बैंक उच्च खुदरा ऋण पूलों (आवास, उपभोक्ता ऋण) और एसएमई की खरीदारी करके भी वित्त कंपनियों की मदद कर रहे हैं।

सितंबर 2018 में आईएलऐंडएफएस की ओर चूक किए जाने के बाद बैंक एनबीएफसी क्षेत्र को अतिरिक्त कर्ज देने में सतर्कता बरतने लगे। अब वे एनबीएफसी को कर्ज प्रदान कर रहे हैं जो आगे खुदरा और एसएमई ऋण देती हैं। दूसरी तरफ बड़े थोक पोर्टफोलियो वाले एनबीएफसी अतिरिक्त रकम जुटाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ऋणदाताओं ने वित्त फर्मों के ऋण प्रोफाइल का निरीक्षण करना भी रोक दिया है और ऋण देने के बदले में पहले से अधिक ब्याज दर और पहले से अधिक जमानती कवर वसूल रहे हैं।

अनिल गुप्ता ने कहा, 'बैंक कर्ज की बढ़ी हुई रकम ज्यादातर एनबीएफसी के पास जा रहा है। इसकी बड़ी वजहों में से एक रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों के लिए किया गया विशेष प्रावधान है जिसके तहत वे एनबीएफसी द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कर्ज देने के लिए उनको ऋण मुहैया करा सकते हैं। इस तरह के ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण मुहैया कराने के बैंकों के लक्ष्यों को पूरा कर पाने में सक्षम होंगे।'

आरबीआई ने पी2पी उधारी सीमा 5 गुना बढ़ाई

निधि राय
मुंबई, 5 दिसंबर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पीयर टु पीयर (पी2पी) प्लेटफॉर्मों पर उधारी की सीमा बढ़ाकर 5 गुना कर दी है। शीर्ष बैंक ने 5 दिसंबर को जारी एक विकासात्मक और नियामकीय नीतियों पर जारी एक बयान में कहा कि कर्जदाता द्वारा सभी उधारी लेने वालों की कुल उधारी किसी भी समय पर सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पीयर टु पीयर प्लेटफॉर्मों पर 50 लाख रुपये तक सीमित होगी, जो अभी 10 लाख रुपये है।

बहरहाल किसी एक उधारी लेने वाले के लिए यह सीमा सभी एनबीएफसी पीयर टु पीयर प्लेटफॉर्मों के लिए 50,000 रुपये बनी रहेगी।

बाजार से जुड़े लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस बहुप्रतीक्षित फैसले से इस क्षेत्र को बल मिलेगा। लेनदेनक्लब के सह संस्थापक और सीईओ भाविन पटेल ने कहा, 'अब पीटूपी उधारी अन्य निवेश विकल्पों जैसे एमएफ, एफडी, बॉन्डों और पीएमएस के बराबर हो गई है। ज्यादातर भारतीय निवेशक इस 50 लाख रुपये की सीमा में आ जाएंगे।'

रुपीसर्किल के सीएफओ और सह संस्थापक अभिषेक गांधी ने कहा, 'यह कदम सभी पी2पी कंपनियों और निवेशकों के लिए बहुत सकारात्मक है, जिससे बाजार की मौजूदा कर्ज की खाईं की समस्या हल करने में मदद मिलेगी। इस घोषणा से निश्चित रूप से पी2पी प्लेटफॉर्मों की ओर ज्यादा निवेशक आकर्षित होंगे। इसके अलावा हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के मौजूदा निवेशक भी अपना निवेश बढ़ाएंगे। साथ ही ज्यादा एचएनआई अब निवेश विकल्प के रूप में पी2पी उधारी की ओर नजर डालेंगे, जो उद्योग के लिए बहुत सकारात्मक संकेत है।'

बीएस सूडोकू 3605 | परिणाम संख्या 3604

		7			8			
3	4					5	9	
	8		9		2		3	
				8			1	7
	3						4	
4	1			9				
	7		4		3		9	
2	6						7	3
			6			1		

7	6	4	5	2	8	1	3	9
2	1	8	9	4	6	3	5	7
3	5	9	7	1	3	6	4	2
1	4	2	6	8	9	7	2	5
5	9	3	2	7	4	8	1	6
6	8	7	1	3	5	2	9	4
4	7	5	8	6	1	9	2	3
8	3	6	4	9	2	5	7	1
9	2	1	3	5	7	4	6	8

कैसे खेलें? हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत आसान ★☆☆☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2110/2120, जौ 1790/1800, चावल मसूरी 2275/2325, चावल मोटा 2150/2250, सरसों 4300/4325, तिल सफेद 9000/9100, सोया (टीन) 1450/1500, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1560/1630,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2100/2125, गेहूं शरबती 2700/2800, चावल शरबती सेला 3800/3900, स्टीम 4300/4400, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2950/3000,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1440, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1530, फ्लैक 1465, डीएमओ 1030, टरपीन लैस बोल्ड 1555

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू नया 950/1075, खुरपा 910/935,चाकू 810/815, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3350, सिहोरा 3180, बुंदकी 3215, बुढ़ाना 3290, चीनी हाजिर 3500/3600

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3650, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 880/890, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4300, खल: सरसों 2250/2350, बिनौला 2400/2500, चना छिलका 1950/2000,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5600/5700, गेहूं (मिल) 2140/2150, मक्की 2050/2100, बाजरा 1820/1825, जौ 1800/1850, ग्वार लूज 3800/3825, ज्वार कैटलफीड 2000/2100, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4590/4600,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2000/2050, ग्वार 3750/3800, जौ 2040/2150,

जोधपुर
गेहूं 2000/2100, जौ 1750/1800, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 3950/4000, ग्वारगम 7300/7350, बाजरा (गुजरात) 1900/1925, बाजरा (जयपुर) 1890/1900, चना 4000/4100, काबली चना 4800/6000, मूंग 6000/6100,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)127, राइसब्रान (अखाद्य) 124, खल सरसों 2080, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1250, लाल 1250, कंटीन्यूअस 1300,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7500/8000, अरहर दाल 7900/8400, उड़द साबुत 7500/8300, उड़द धोया 9500/10000, छिलका 9000/10000, दाल मसूर 5500/5800, चनादाल 5400/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6500/6600, सेला 5700/5800, शरबती साधारण सेला 3900/4000, शरबती स्टीम 4400/4500,चावल 1509 सेला 5200/5300, धान: शरबती 2100/2150,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब नई 3925/3960, हरियाणा 3900/3925, राजस्थान 3850/3925, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2300/2400, सरसों खल 2170/2180,

फाजिल्का
गेहूं 2140/2150, सरसों 4350/4400 रुई (प्रति मन): (जे-34) 3900/3950,कपास देशी 4900/5000, कपास नरमा (क्विं.) 5100/5200, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2300/2400,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2130/2140, चावल परमल कच्चा 2450/2500, से ला 2375/2400, मक्की यूपी 2175/2200, बिहार 2325/2335, दाल उड़द छिलका 9000/10500, चना देशी 5250/5350, दाल चना 5400/5500, काबली चना 5000/6000, राजमां चित्रा पुणे 7000/8600, चीन 7400/8000,

करनाल
गेहूं दड़ा 2140/2150, बासमती चावल 6600/6700, धान 1121 नं. 2800/2900, पूसा 1509 धान 2500/2650, शरबती धान 2100/2150, सेला (1509 नं.) चावल 5300/5400, स्टीम 6400/6500,

हिसार
ग्वार 3800/3850, सरसों 4100/4150, गेहूं 2140/2145, नरमा कपास 4900/5000

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2150, आटा (प्रति 44 किलो) 1070/1090, मैदा 1175/1190, देशी घी (एक ली/जार) 370/470, रिफाइंड (टीन) 1385/1400,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4100/4150, खल बिनौला मोटी 2200/2300, बिनौला 2400/3100, सरसों तेल 8750/8800, गेहूं 2100/2200, ग्वार 3750/3800, बाजरा 1800/1900 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 249

बजट होगा निर्धारक

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने गुरुवार को नीतिगत रीपो दर में कटौती न करके वित्तीय बाजार को चौंका दिया। हाल की तिमाहियों में आर्थिक वृद्धि दर में तेजी से गिरावट आई है जिसके बाद एक बार फिर दरों में कटौती की अपेक्षा बढ़ गई थी। परंतु समिति के पास भी कटौती न करने की अहम वजह थीं। जैसा कि इस समाचार पत्र ने पहले भी कहा था, दरों में कटौती के पक्ष में एकमात्र दलील यह थी कि यथास्थिति वाली नीति वित्तीय बाजार में घबराहट पैदा कर सकती है।

यह सही है कि आर्थिक विस्तार की गति पिछली कुछ तिमाहियों में तेजी से कम हुई है। यह भी कहा जा सकता है कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत मुद्रास्फीति के लक्ष्यों को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित है। खासतौर पर तब जबकि अन्य केंद्रीय बैंक अपने प्रभाव को लेकर स्वयं सवाल उठा रहे हैं। परंतु आरबीआई ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। वह मुद्रास्फीति से जंग जारी रखना चाहता है। वर्ष की दूसरी छमाही के लिए उसने मुद्रास्फीति को लेकर अपना अनुमान भी संशोधित करके 5.1 से 4.7 फीसदी कर दिया है। हालांकि शीर्ष मुद्रास्फीति के लिए खाद्य कीमतें ही प्रमुख कारक हैं और केंद्रीय बैंक को आशा है कि अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही में इसमें कमी आ जाएगी लेकिन फिर भी उसने अधिक स्पष्टता के लिए प्रतीक्षा करना बेहतर समझा। आम घरों के मुद्रास्फीति संबंधी अनुमान यह संकेत देते हैं कि मुद्रास्फीतिक दबाव की अनदेखी करने के अपने जोखिम हैं। इसके अलावा खाद्य मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान लगाना हमेशा कठिन होता है। केंद्रीय बैंक द्वारा हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति के अतिरंजित अनुमान की एक वजह खाद्य मुद्रास्फीति का सही अनुमान न लगा पाना भी रहा है। यकीनन वह ऐसे समय पर नीतिगत चूक नहीं करना चाहेगा जब खाद्य कीमतें बढ़ रही हैं। इसके अतिरिक्त एक ओर जहां आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास नीति प्रस्तुत किए जाने के बाद मीडिया के साथ चर्चा में वास्तविक ब्याज दरों पर सवाल का जवाब देने से बचे, वहीं संभव है कि एमपीसी की चर्चा में इसका जिक्र मिले।

एमपीसी ने मौजूदा आर्थिक हालात में सरकारी नीति पर अधिक स्पष्टता के लिए बजट की प्रतीक्षा करने का एकदम सही निर्णय लिया है। हालांकि केंद्रीय बैंक राजकोषीय परिस्थितियों को लेकर अपनी चिंताएं स्पष्ट रूप से प्रकट करने से बचा है लेकिन राजस्व के मोर्चे पर सरकार की स्थिति निश्चित रूप से चिंताजनक है। ऐसे में केंद्रीय बैंक को राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के बीच संतुलन रखने के लिए प्रयास करना होगा। बहरहाल, नीतिगत दरों में कटौती का शायद वांछित असर नहीं होता क्योंकि अधिकांश निवेशक सरकार से यह अपेक्षा नहीं करते कि वह घोषित राजकोषीय घाटा लक्ष्य पर टिकी रहेगी।

आखिर में, हालांकि बॉन्ड बाजार के एक हिस्से ने चालू दौर में नीतिगत दरों में कटौती को लेकर प्रतिक्रिया दी किंतु बैंकों की ऋण दर में इसका पारेषण बहुत धीमी गति से हुआ। एमपीसी का समायोजन भरा रुख और नकदी की मौजूदगी की वजह से यह प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। इस मोड़ पर दरों में कटौती पारेषण को प्रभावित कर सकता था क्योंकि बाजार इसे सहजता के चक्र के समापन के करीब आने के रूप में देख सकता था। ऐसे में एमपीसी का कदम समझदारी भरा है। मुद्रास्फीति के अलावा मौद्रिक नीति का अगला कदम बजट पर भी निर्भर होगा। बजट एमपीसी की फरवरी की बैठक के पहले पेश होगा। सरकार के सामने फिलहाल कई राजकोषीय चुनौतियां हैं। चालू वर्ष में राजकोषीय फिसलन एमपीसी को आगे और शिथिलता बरतने से रोक सकता है। इसके अलावा फिलहाल ठहराव यह भी दिखाता है कि एमपीसी अपने पास मौजूद नीतिगत गुंजाइश का समुचित प्रयोग करेगी।

अजय मोहंती

आर्थिक रसूख का कूटनीतिक प्रयोग

भारत के लिए इस बदलती कूटनीतिक शैली के अपने जोखिम हैं। यदि इससे ठीक तरीके से नहीं निपटा गया तो गंभीर वैश्विक प्रतिभागी होने की भारत की छवि दांव पर लग जाएगी। विस्तार से बता रहे हैं **हर्ष वी पंत**

इसमें दो राय नहीं कि बीते कुछ वर्षों में भारतीय कूटनीति का तेजी से उद्भव हुआ है। कुछ मायनों में यह वैसा ही है जैसा कि इसे होना चाहिए। प्रभावी कूटनीति का अर्थ ही होता है तमाम तरह के दबावों और अन्य परिस्थितियों में समय पर उचित प्रतिक्रिया देना। हाल के महीनों में देश की कूटनीति में एक नए किस्म की धार देखने को मिली है। यह देश के हितों को नुकसान पहुंचाने वालों से खुलकर निपटने को तैयार दिखी है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खात्मा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। ऐसा करके सरकार ने न केवल इस क्षेत्र का संवैधानिक स्वरूप बदल दिया बल्कि आजादी के समय से चली आ रही यथास्थिति भी समाप्त कर दी। उम्मीद के मुताबिक ही इस निर्णय के बाद वैश्विक स्तर पर इसकी प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है।

ज्यादातर देश भारत के साथ सहानुभूति रखते हैं और वे भारत की इस बात से सहमत हैं कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है। वहीं कुछ देशों ने पाकिस्तान का पक्ष भी लिया। चीन एक बड़ी समस्या बना हुआ है। उसने कहा कि भारत ने अपने घरेलू कानून में एकतरफा बदलाव करके और प्रशासनिक निर्णयों के माध्यम से उसकी संप्रभुता और उसके हितों को नुकसान पहुंचाया है। कुछ अन्य देश भी पाकिस्तान के साथ आए।

गत माह संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्डोगन ने भारत के इस कदम की आलोचना की और पाकिस्तान के नजरिये का समर्थन करते हुए कहा कि कश्मीर के लोग लगभग बंदी की स्थिति में हैं और 80 लाख लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में समस्या का समाधान न्याय और समता पूर्ण संवाद के माध्यम से ही हो सकता है न कि टकराव से। एर्डोगन ने यह भी कहा कि दक्षिण एशिया की स्थिरता और समृद्धि कश्मीर मुद्दे से अलग नहीं हो सकती।

आक्रामक कूटनीति

भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया एकदम ठोस थी। उसने तुर्की की सरकार से कहा कि वह कश्मीरी की जमीनी परिस्थितियों की सही समझ पैदा करने के बाद ही इस विषय पर आगे कोई टिप्पणी करे। उससे कहा गया कि कश्मीर मसला भारत का आंतरिक मसला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की के प्रतिद्वंद्वी ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। जाहिर है एर्डोगन इस संदेश की अनदेखी नहीं कर पाए होंगे।

भारत ने न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित तुर्की यात्रा को रद्द कर दिया बल्कि तुर्की की कंपनी एनाडोलु शिपयार्ड को भारत में रक्षा संबंधी कारोबार करने से भी रोक दिया गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने एनाडोलु शिपयार्ड को भारतीय नौसेना के दो अरब डॉलर मूल्य के सहयोगी जहाजी बेड़े की परियोजना में तकनीकी साझेदार के रूप में चुना था। परंतु तुर्की और पाकिस्तान के रिश्तों के चलते भारत को इस अहम परियोजना में उसे शामिल करने को लेकर अपनी अनिच्छा दर्शाने पर मजबूर किया। इसके बाद भारत ने उत्तरी सीरिया में तुर्की की सैन्य कार्रवाई की आलोचना की। भारत ने कहा कि इससे क्षेत्र की स्थिरता और आतंक के खिलाफ लड़ाई को खतरा उत्पन्न हो सकता है। भारत ने तुर्की से कहा कि वह सीरिया की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे।

मलेशिया द्वारा कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का समर्थन करने पर भी भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। हालांकि यह प्रतिक्रिया तुर्की की तुलना में नरम थी। मलेशिया से भारत की नाराजगी मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के ट्वीट से संबंधित थी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस कदम के पीछे कई वजह हो सकती हैं लेकिन फिर भी यह कदम गलत है। कश्मीर को लेकर उपजे तनाव से इतर भारत और मलेशिया के बीच तनाव की एक और वजह कट्टर इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक भी है। भारत मलेशिया से नाइक का प्रत्यर्पण करना चाहता है। भारत मलेशिया पर सीधा हमला करने से बचता रहा लेकिन देश की सबसे शीर्ष खाद्य तेल व्यापार संस्था ने अपने सदस्यों से कहा कि वे मलेशिया से पाम ऑयल न खरीदें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है। ऐसे में माना गया कि वह अन्य वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की ओर देख रहा था। करीब एक महीने के अंतराल के बाद भारत की रिफाइनरियों ने मलेशियाई पाम ऑयल की खरीदारी शुरू की।

बदलती कूटनीतिक शैली

ये तमाम कदम बताते हैं कि भारत अपने हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों से निपटने के लिए तैयार है। भारत के मित्रों और शत्रुओं की बात करें तो दोनों के लिए संदेश एकदम स्पष्ट है कि अगर भारत जैसे दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था के साथ लाभकारी द्विपक्षीय साझेदारी कायम करनी है तो कुछ सीमाओं का ध्यान रखना होगा। यह भारत जैसे देश के लिए एक अहम बदलाव है जो अब तक तमाम देशों के साथ सामरिक समझौतों पर हस्ताक्षर करके प्रसन्न था। इस कदर समझौते हुए कि यह शब्द अपने मानी ही गंवा बैठा। इनमें से ज्यादातर समझौते न तो सामरिक हैं न ही इन्हें सही अर्थों में समझौता कहा जा सकता है।

परंतु इस बदलाव के भारत के लिए भी कुछ जोखिम हैं। यदि इसे ठीक तरह से नहीं संभाला गया तो एक गंभीर वैश्विक प्रतिभागी के रूप में भारत की छवि भी दांव पर लग जाएगी। आलोचक चीन का उदाहरण सामने रखेंगे जहां भारत ने बीच का रास्ता अपनाना चाहा ताकि एक ओर चीन के साथ संबंध कायम रखे जाएं और कई तरह से अपनी नाखुशी भी जाहिर की जाए। परंतु यह दलील कई तरह से गलत है। चीन भी अमेरिका और भारत जैसे अलग-अलग मुल्कों के साथ अलग-अलग व्यवहार करता है। शक्तिसंपन्नता ऐसी हकीकत है जो एक देश के अन्य देशों के साथ कूटनयिक रिश्तों को प्रभावित करता है।

अपनी आर्थिक शक्ति के इस कूटनयिक इस्तेमाल का यह नया प्रयास देश की कूटनीति को लेकर एक नई राह खोलता है जिसे लेकर परंपरावादी शायद बहुत अधिक सहज न हों। परंतु भारत के आर्थिक उभार के साथ यह भी एक तरीका है जिससे भारत अपने हितों की न केवल रक्षा कर सकता है बल्कि उसमें इजाफा भी कर सकता है। भारत को इसका इस्तेमाल करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए।

मोदी सरकार के लिए मुफीद है राहुल बजाज की टिप्पणी

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

वरिष्ठ उद्योगपति राहुल बजाज ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सामने एक अहम सवाल खड़ा किया है। आखिर उद्योग जगत, मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ बोलने को लेकर भयभीत क्यों है? मोदी सरकार के कार्यकाल में इतना डर का माहौल क्यों है कि उद्योगपति सरकार को लेकर आलोचनात्मक टिप्पणी करने से भी घबरा रहे हैं? बजाज ने कहा कि तुलनात्मक रूप से देखें तो यही उद्योग जगत, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने से नहीं घबराता था। मोदी सरकार ने बजाज की बातों को काफी गंभीरता से लिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसी कोई वजह नहीं जिससे उद्योग जगत माने कि भय का वातावरण है। परंतु चूंकि ऐसी टिप्पणी की गई है तो सरकार देखेगी कि क्या सुधार किए जा सकते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सवालों का जवाब चाहना हमेशा अपनी धारणाओं को फैलाने से बेहतर होता है क्योंकि इससे राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंच सकता है। रेल एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल उठाए जाने का अर्थ ही है कि भय का कोई वातावरण नहीं। आवास, शहरी मामलों और नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि बजाज के जैसे वक्तव्य झूठा माहौल तैयार करते हैं।

बजाज ने गत सप्ताह मुंबई में देश के उद्योग जगत की शीर्ष हस्तियों और मंचासीन वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी में जो कुछ कहा उसके संदर्भ और निहितार्थ की पड़ताल जरूरी है।

ध्यान रहे कि 80 वर्ष की उम्र के इस उद्योगपति ने अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी के आरंभ में कहा कि मोदी सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है। परंतु वह इस बात से दुखी थे कि उद्योग जगत के लोग इस बात को लेकर निश्चित नहीं थे कि सरकार के प्रति उनकी आलोचनात्मक टिप्पणी की सराहना होगी या नहीं और सरकार उसे ठीक से लेगी या नहीं। यह, मोदी सरकार के आर्थिक चुनौतियों से निपटने के तरीके की आम आलोचना से अलग है। बजाज की आलोचना मौजूदा आर्थिक मंदी से उपजी चुनौतियों से निपटने के सरकार के तौर तरीकों पर केंद्रित नहीं थी। बजाज उस बॉम्बे क्लब के संस्थापक सदस्य थे जिसने सन 1990 के आरंभ में मांग की थी आर्थिक खुलापन आने के बाद देश के घरेलू उद्योग जगत के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों से बचाव सुनिश्चित किया जाए। बजाज मोदी सरकार के टैरिफ बढ़ाने या दुनिया की सबसे बड़ी व्यापार व्यवस्था बन सकने वाले व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी (आरसेप) से बाहर आने को लेकर असहज नहीं थे।

आलोचना मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर केंद्रित नहीं थी बल्कि वह इस बात के खिलाफ थे कि सरकार उद्योग जगत की प्रतिपुष्टि सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक कि उद्योग जगत अब आलोचना करने से भी घबरा रहा है। बायोकॉन की चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक किरण मजूमदार शॉ ने बजाज की बातों का समर्थन किया और आशा जताई कि सरकार अब उद्योग जगत से इस विषय पर चर्चा करेगी कि आर्थिक वृद्धि में सुधार कैसे किया जाए। शॉ ने सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणी में कहा कि अब तक सरकार अर्थव्यवस्था की आलोचना नहीं सुनना चाह रही थी। ऐसे में बजाज दरअसल यह कहना चाह रहे थे कि मोदी सरकार को उद्योग जगत के नेताओं और सत्ता प्रतिष्ठान के बीच संवाद कायम करना चाहिए। वह कारोबारियों की यह इच्छा सामने रख रहे थे कि सरकार और कारोबारियों के बीच संबद्धता नए सिरे से तय होनी चाहिए। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के शुरुआती दिनों में इन शर्तों को नए ढंग से तय किया गया था। उद्योग जगत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की सराहना की थी। उसे लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और अधिक आर्थिक सुधार लाएंगे। अपेक्षाओं के अनुरूप मोदी ने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन का कड़ा प्रयास किया लेकिन बढ़ते राजनीतिक प्रतिरोध के चलते उन्हें पीछे हटना पड़ा। पहले कार्यकाल के बचे हुए वक्त में मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर, अचल संपत्ति नियमन और ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया निस्तारण जैसे कई अहम सुधार किए। दूसरे कार्यकाल में भी मोदी सरकार ने कॉर्पोरेशन कर दर में कमी और महत्त्वाकांक्षी निजीकरण कार्यक्रम के माध्यम से साहसी कदम उठाए।

परंतु यह स्पष्ट होता जा रहा था कि मोदी सरकार उद्योग जगत के करीब दिखना नहीं चाहती। इसलिए क्योंकि उद्योग जगत के बहुत करीब दिखने के राजनीतिक जोखिम हैं और इससे भाजपा को राजनीतिक नुकसान हो सकता था। ऐसी स्थिति में बजाज का यह कहना कि उद्योग जगत के लोग सरकार की आलोचना करने से डरते हैं, दरअसल भाजपा की इस राजनीतिक छवि को मजबूत करता है कि वह उद्योग जगत से दूर है। यहां तक कि 2019 के आम चुनाव में ज्यादा बहुमत से सत्ता में आने के बाद भी भाजपा नेतृत्व निरंतर अपनी राजनीतिक पूंजी और छाप मजबूत करने में लगा हुआ है।

ऐसा इसलिए कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन उसके लिए एक झटका साबित हुआ। उसे आगामी विधानसभा चुनावों में जबरदस्त जीत की आवश्यकता है। वह एक ऐसी सरकार के रूप में दिखना चाहती है जिसके उद्योग जगत के साथ करीबी रिश्ते नहीं हैं। नतीजा? उद्योग जगत के लोगों का सरकारी नीतियों के खिलाफ बोलने से डरना आगामी चुनावों में उसे राजनीतिक रूप से लाभ पहुंचा सकता है। बजाज की बातों ने इस छवि को मजबूत किया है।

तथ्य यह है कि उद्योग जगत और सरकार के करीबी रिश्ते भाजपा को चुनाव नहीं जिता सकते। इसके विपरीत उद्योग जगत यदि भाजपा सरकार के साथ सहज है और उसके साथ मित्रतापूर्ण रिश्ता रखता है तो इसका पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर बुरा असर हो सकता है। विपक्षी दल मोदी सरकार को लेकर बजाज की आलोचना से खुश हो सकते हैं लेकिन भाजपा को इसे राजनीतिक वरदान मानना चाहिए।

कानाफूसी

फंड की कमी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ अतीत में कह चुके हैं कि गत वर्ष दिसंबर में जब कांग्रेस ने सरकार बनाई तब प्रदेश की वित्तीय स्थिति एकदम खस्ता हालत में थी। एक वर्ष बीतने के बाद भी हालात में सुधार नहीं हुआ है। सरकार अभी भी विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए संघर्ष कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, भोपाल-इंदौर सिक्सलेन एक्सप्रेसवे और तमाम परियोजनाएं फंड के इंतजार में स्थगित हैं। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग की भी यही हालत है। सरकार ने पैसे के अभाव में भोपाल-इंदौर एक्सप्रेसवे का विचार ही त्याग दिया है क्योंकि परियोजना के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इससे पहले जुलाई 2019 में राज्य का बजट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री तरुण भनोत ने पिछली भाजपा सरकार की शाहखर्ची की जमकर आलोचना की थी।

सब एक साथ

पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की 100वीं जयंती के अवसर पर बुधवार को राजधानी नई दिल्ली में तमाम विचारधाराओं के राजनेता एकत्रित हुए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार इस मौके पर आकर्षण का केंद्र बने हुए थे और तमाम राजनेता हाल ही में महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर उन्हें बधाई देने उनके पास पहुंचे। महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम के बाद एक महीने तक सरकार का गठन नहीं हो पाया था जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया। बाद में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी। दिल्ली में यातायात की स्थिति को लेकर चुटकुले भी साझा किए गए। जब वहां मौजूद लोगों को पता चला कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी भी जाम में फंस गए थे तो लोगों की हंसी नहीं रुक रही थी। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बातचीत करते देखे गए।

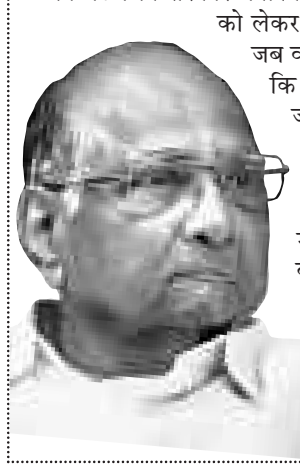

शरद पवार

आपका पक्ष

साइबर क्राइम के खिलाफ उठे आवाज

वर्तमान में तकनीक ने जिस तेजी के साथ जीवन में दखल देना शुरू किया है उसी तेजी से मानवीय मूल्यों पर असर दिखाई पड़ रहा है। व्यक्ति में आदर्शों, मूल्यों और ज्ञान-विज्ञान की अथाह पूंजी के साथ-साथ मानवीय कुंठाएं और आपराधिक व्यवहार भी गति पकड़ रही है। जाहिर तौर पर इसका सबसे ज्यादा शिकार आधी आबादी हो रही है। ऑनलाइन प्रताड़ना, पहचान की चोरी, ईमेल स्पूफिंग, साइबर स्टॉकिंग और ऑनलाइन बुलिंग जैसे शब्दों का चलन अब हमारे बीच आम होने की स्थिति में है। आजकल सुरक्षा के सवाल को लेकर महिलाएं कहीं भी निश्चिंत नहीं हैं। महिलाएं न तो असल दुनिया में और न ही आभासी दुनिया में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाओं के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल से लेकर शारीरिक शोषण तक किसी भी अनहोनी के होने की दहशत और आशंका हर पल मौजूद है। ऑनलाइन प्रताड़ना

की चपेट में अधिकतर ऐसी महिलाएं आती हैं जो सतही जानकारियों के साथ-साथ इस मायावी दुनिया में जी रही हैं। ऐसी महिलाएं जो तकनीक की दुनिया का हिस्सा तो बन जाती हैं लेकिन अपनी सुरक्षा के हिस्से का उपयोग करना नहीं सीख पातीं हैं। अर्थात ऐसी महिलाएं तकनीक और कानून द्वारा दी गई सुरक्षा सुविधाओं से

महिलाओं को अपने ऊपर हो रहे साइबर क्राइम के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए

वाकिफ नहीं होती हैं। यह जरूरी नहीं कि हर मामले में पीड़िता को उलझाया ही गया हो। कई मामलों में पीड़िता भावुक, स्वप्नदर्शी और महत्त्वकांक्षी महिलाएं खुद उलझ जाती हैं। साइबर क्राइम विशेषज्ञों के मुताबिक 70 प्रतिशत महिलाएं अश्लील मेसेज, अभद्र और पोर्नोग्राफिक सामग्री पर टैगिंग की गुपचुप शिकायतें करती हैं। लेकिन कानून की मदद नहीं लेती हैं जिससे निश्चित रूप से साइबर क्राइम के स्टॉकर्स को इसके प्रति बढ़ावा मिलता है। इसलिए महिलाओं को साइबर क्राइम के प्रति खुल कर सामने आने की कोशिश करनी चाहिए जिससे वह फिर कभी इसकी चपेट में नहीं आएं।

हरिओम हंसराज, छपरा

प्याज की कीमत पर देश में उबाल

प्याज के दाम 100 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक हो गए हैं। देश भर में प्याज के बढ़े दाम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्याज के दाम में बढ़ोतरी का कारण बेमौसम बारिश, मंडियों से प्याज की आवक का नहीं होना, प्याज सड़ जाना आदि बताया जा रहा है। इसी साल के शुरुआत में किसान प्याज के उचित दाम नहीं मिलने से खफा होकर सड़कों पर प्याज फेंक रहे थे। देश के विभिन्न जगहों पर किसान सड़कों पर प्याज बिखेर कर विरोध जता रहे थे और प्याज की उचित दाम की मांग कर रहे थे। आज भी प्याज के 100 रुपये से अधिक होने पर इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। किसानों से लेकर उपभोक्ताओं के बीच बिचौलिया तंत्र ही प्याज के बढ़े दाम का लाभ उठाता रहा है। अगर उस वक्त सरकार किसानों से उचित मूल्य पर प्याज खरीद कर भंडारण करती तो आज प्याज के दाम इतने नहीं बढ़े होते। अत: सरकार को किसानों से अनाज की सीधे खरीदारी कर भंडारण करना चाहिए जो भविष्य के लिए सुरक्षित हो जाए। इससे अनाज की कीमत साल भर समान रहेगी तथा अनाज की कालाबाजारी तथा बिचौलिये पर लगाम लगेगी।

राजेश कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

चाय निर्यात बाजार के रूप में उभर रहा ईरान

ईरान को चाय निर्यात इस साल सितंबर तक 4.376 करोड़ किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 5 दिसंबर

व्यापार पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान रूस को पीछे छोड़कर इस साल भारत का शीर्ष चाय निर्यातक देश बनने जा रहा है। ईरान को किया जाने वाला निर्यात इस साल सितंबर तक 4.376 करोड़ किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और भारत ने 17.284 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

सूत्रों ने कहा कि ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण श्रीलंका जैसे अन्य निर्यातक देशों के लिए अपना निर्यात बनाए रखना मुश्किल हो गया है। प्रतिबंध लगाए जाने के बाद खास तौर पर इस बात को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है कि ईरान में विदेशी मुद्रा की कमी होने की वजह से भुगतान कैसे किया जाएगा। हालांकि भारत और ईरान के बीच व्यापारिक समझौते के तहत ईरान भारत को किए जाने वाले तेल निर्यात के बदले भारत से अपने आयात के लिए रुपये में भुगतान कर सकता है। तेल का भुगतान ईरान की मुद्रा रियाल में किया जाता है।

ईरान को प्रत्यक्ष रूप से बड़ी मात्रा में चाय निर्यात करने वाले एक उत्पादक ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि इस व्यापारिक समझौते से भारत को न केवल बाजार बनाए रखने में मदद मिली है, बल्कि इसका विस्तार भी हुआ है। जहां एक ओर दूसरे देशों से किए जाने वाले निर्यात को अनिश्चितता का सामना करना पड़ा है, वहीं भारतीय निर्यातक प्रतिस्पर्धा खत्म करने और बाजार की हिस्सेदारी पाने में सफल रहे हैं।

देश का चाय निर्यात

देश	मात्रा*	कुल विदेशी मुद्रा प्राप्ति	इकाई मूल्य (डॉलर प्रति किलो)
ईरान	4.376	17.284	3.95
सीआईएस	4.172	9.781	2.34

*जनवरी से सितंबर तक (करोड़ किलोग्राम में), **करोड़ डॉलर,
स्रोत : भारतीय चाय बोर्ड

- ईरान को चाय निर्यात कर भारत ने 17.284 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित की
- भारत ने अपना ध्यान ईरान और निर्यात बढ़ाने पर केंद्रित रखा जिससे श्रीलंका का ईरान को किया जाने वाला चाय निर्यात 9.52 फीसदी गिरा
- निर्यात के दामों में भी इजाफा हुआ है जिसका मुख्य कारण गुणवत्ता में सुधार होना है

जनवरी से अक्टूबर की अवधि के दौरान चूंकि भारत ने अपना ध्यान ईरान और निर्यात बढ़ाने पर केंद्रित रखा था इसलिए श्रीलंका का ईरान को किया जाने वाला चाय निर्यात 9.52 प्रतिशत तक गिरकर 1.827 करोड़ रह गया। चाय बोर्ड से मिले आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से सितंबर के दौरान भारत से ईरान को किया जाने वाला चाय निर्यात 115.67 प्रतिशत तक बढ़कर 4.376 करोड़ किलोग्राम के स्तर तक पहुंच गया, जबकि विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्ति 133.38 प्रतिशत उछलकर 17.284 करोड़ डॉलर हो गई।

इसकी तुलना में रूस और अन्य सीआईएस देशों को किया जाने वाला निर्यात 11.46 प्रतिशत तक गिरकर 4.172 करोड़ किलोग्राम रह गया और विदेशी मुद्रा प्राप्ति 12.99 प्रतिशत घटकर 9.781 करोड़ डॉलर रह गई। ऐतिहासिक रूप में रूस भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार रहा है तथा कुल भारतीय चाय निर्यात में रूस और सीआईएस का संयुक्त योगदान आमतौर पर 25 से 30 प्रतिशत रहा है। हालांकि इस साल सितंबर तक किए गए कुल 18.252 करोड़ किलोग्राम निर्यात में रूस और सीआईएस को किया जाने वाला निर्यात 22.85 प्रतिशत रहा, जबकि ईरान को किए जाने वाले निर्यात का योगदान 23.97 प्रतिशत रहा। इस थोड़े-से अंतर के बावजूद ईरान से होने वाली कमाई रूस और सीआईएस की तुलना में काफी आगे रही।

भारतीय चाय व्यापार में मूल्य के हिसाब से ईरान का योगदान 29.19 प्रतिशत रहा, जबकि रूस का योगदान 16.52 प्रतिशत रहा। मौजूदा कारोबारी परिदृश्य का विश्लेषण करने से पता चलता है कि निर्यातकों का मानना है कि इस साल ईरान शीर्ष स्थान पर रहगा और भारत के सबसे बड़े चाय निर्यात गंतव्य के रूप में उभरेगा तथा इस दौड़ में रूस दूसरे स्थान पर रहेगा।

चाय बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन एके रे ने कहा कि यहां खास बात यह है कि निर्यात के दामों में भी इजाफा हुआ है। रे के अनुसार इस दाम वृद्धि के पीछे कारण गुणवत्ता में सुधार होना रहा है। बोर्ड ने चाय की गुणवत्ता में सुधार के लिए पिछले साल बागान बंद करना अनिवार्य कर दिया था और इस साल भी इसी प्रकार का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा बोर्ड चाय की गुणवत्ता की लगातार निगरानी तथा खराब चाय को नष्ट कर रहा है।

आपूर्ति बढ़ने से चावल के दाम तीन साल के निचले स्तर पर

रॉयटर्स
बेंगलूरु, 5 दिसंबर

शीर्ष निर्यातक देश भारत में इस सप्ताह चावल के दाम गिरकर तीन साल के निचले स्तर पर आ गए हैं क्योंकि हालिया फसल कटाई से हुई पर्याप्त आपूर्ति के कारण मांग कमजोर हो गई है, जबकि फिलीपींस ने चावल की वियतनामी किस्म के लिए मांग में इजाफा किया है। इस सप्ताह भारत के पांच प्रतिशत टूटे उसने किस्म के चावल के दाम प्रति टन 356 से 361 डॉलर के आस-पास बोले गए हैं जो जनवरी 2017 के बाद से सबसे कम स्तर है, जबकि पिछले सप्ताह दाम 358 से 362 डॉलर के बीच थे। आंध्र प्रदेश के काकिनाडा में एक निर्यातक ने कहा कि नई फसल से आपूर्ति में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन मांग नहीं बढ़ रही है।

- इस सप्ताह बांग्लादेश के घरेलू दामों में आई नरमी
- अक्टूबर के दैरान भारत का चावल निर्यात 42 प्रतिशत गिरा

आज सरकारी आंकड़ों से जानकारी मिली है कि अफ्रीकी देशों की ओर से गैर-बासमती किस्म वाले चावल की कमजोर मांग के कारण अक्टूबर में देश का चावल निर्यात पिछले साल के मुकाबले 42 प्रतिशत गिरकर 4,85,898 टन रह गया है। भारतीय निर्यातकों के अनुसार देश के निर्यात में कमी आने से थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार जैसे प्रतिस्पर्धी देशों को अपना निर्यात बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

वियतनाम में पांच प्रतिशत टूटे चावल के दाम आज प्रति टन 345 डॉलर बोले गए हैं, जबकि एक सप्ताह पहले दाम 345 से 359 डॉलर के दायरे में थे। हो ची मिन्ह शहर स्थित एक कारोबारी ने कहा कि फिलीपींस की ओर से ज्यादा ऑर्डर मिलने के कारण मांग जोर पकड़ रही है। कारोबारी ने यह भी कहा कि इस बीच निर्यातक इराक और क्यूबा के ग्राहकों के साथ पहले किए गए सौदों के ऑर्डर पूरे करने पर ध्यान दे रहे हैं।

वियतनाम के सबसे बड़े चावल उत्पाद क्षेत्र मेकॉन्ग डेल्टा में किसान सर्दी-बसंत की प्रमुख फसल के लिए खेत तैयार कर रहे हैं, लेकिन कारोबारियों को डर है कि शायद फसल की गुणवत्ता पहले जैसी न रहे है। बांग्लादेश सरकार द्वारा गलत ढंग से काम करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की घोषणा और प्रमुख उत्पादों के आयात शुल्क में कटौती पर विचार करने के बाद इस सप्ताह चावल के घरेलू दामों में कुछ गिरावट आई है।

भारत गैर-बासमती चावल का निर्यात मुख्य रूप से बांग्लादेश, नेपाल, बेनिन और सेनेगल को तथा बढ़िया बासमती चावल का निर्यात ईरान, सऊदी अरब और इराक को करता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2019-20 के पहले सात महीनों के दौरान इसका निर्यात 28 प्रतिशत गिरकर 48.5 लाख टन रह गया।

चावल निर्यातक संघ के अध्यक्ष बीवी कृष्ण राव ने कहा कि स्थानीय दामों में अधिकता की वजह से दुनिया में भारतीय चावल अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमता गंवा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को विदेशी बिक्री बढ़ाने के लिए सब्सिडी उपलब्ध करानी चाहिए वरना निर्यात कमजोर बना रहेगा।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Dec 5	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,771.0	0.9	1,893.7	-3.5
Copper	5,823.0	0.8	6,228.1	1.2
Nickel	13,250.0	-24.5	14,167.5	-21.7
Lead	1,900.0	-8.0	2,132.1	4.2
Tin	16,850.0	-2.0	17,604.2	-3.4
Zinc	2,256.5	-4.0	2,595.0	-1.3
Gold ($/ounce)	1,476.6*	-2.8	1,659.1	-1.7
Silver ($/ounce)	16.9*	-9.3	19.2	-10.8
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	63.3*	3.4	61.9	3.5
Natural Gas ($/mmBtu)	2.4*	-0.4	2.4	-0.1
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	186.6	12.7	298.8	5.6
Maize	182.6*	2.4	313.6	6.0
Sugar	346.5*	14.5	484.2	-1.4
Palm oil	665.0	24.9	1,058.6	21.7
Rubber	1,596.6*	3.5	1,823.5	-7.1
Coffee Robusta	1,356.0*	8.6	1,886.7	-7.8
Cotton	1,426.4	9.4	1,573.5	-1.3

* As on Dec 05, 19 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.3& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	20.4	12201
Oil and Oilseeds	146.4	67670
Spices	1.1	14
Metal(Dec 04)		
Metal- non ferrous	5860.9	59645
Metal- precious	12335.2	468
Oil and gas(Dec 04)		
Gas	3236.2	40365
Oil	18243.3	2851

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	160.6	112268
Grains	278.9	102985
Oil and Oilseeds	619.8	499160
Others	189.3	67650
Pulses	97.8	62105
Spices	88.5	31987

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Crude Oil (Dec 18)	4184.0	3.6
Crude Oil Mumbai (Dec 18)	4184.0	3.6
Cardamom (Dec 13)	3006.7	3.1
Zinc (Dec 31)	184.0	1.4
Zinc Mini (Dec 31)	184.2	1.2
Losers (* % Change)		
Natural Gas (Dec 26)	171.3	-4.7
Silver Mini (Feb 28)	44454.0	-1.9
Silver Micro (Feb 28)	44459.0	-1.9
Nickel (Dec 31)	969.7	-1.7
Silver (Dec 05)	44392.0	-0.5
Gold Guinea (Dec 31)	30592.0	-0.4
Aluminium Mini (Dec 31)	133.2	-0.3

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Coriander-Kota (Dec 20)	6790.0	2.9
GuarGum 5T-Jodhpur (Dec 20)	7297.0	2.2
Guar Seed 10 (Dec 20)	4044.0	2.0
CastorSeed New-Disa (Dec 20)	4112.0	1.9
Moong-Mertacity (Dec 20)	6700.0	1.5
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	5650.0	1.0
Mustard Seed Rape Oil (Dec 20)	4392.0	0.7
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Dec 20)	832.8	0.5
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1071.0	0.4
Losers (* % Change)		
CottonSeed Oil-Akola (Dec 20)	1925.0	-0.9
Soyabean Indore (Dec 20)	4098.0	-0.2
Maize Kharif (Dec 20)	2031.0	0.0

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Cardamom Vandanmedu (Dec 13)	3006.7	4.7
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1043.0	4.4
Cotton-Rajkot (Dec 31)	19070.0	2.5
Gold Petal-Mumbai (Dec 31)	3881.0	1.6
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	44459.0	1.3
Silver Ahm (Dec 05)	44392.0	1.1
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Dec 31)	1299.8	-7.6
Alumini-Mumbai (Dec 31)	133.2	-4.0
Aluminium Mum (Dec 31)	133.2	-3.9
Lead Mum (Dec 31)	152.8	-3.6
Lead Min Mumbai (Dec 31)	152.8	-3.5
Copper Mum (Dec 31)	431.1	-3.0

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Dec 20)	7297.0	1.5
Maize-Sangli (Dec 20)	2031.0	1.0
Soy Bean Indore (Dec 20)	4098.0	0.4
Barley Jaipur (Dec 20)	2123.5	0.2
29 mm Cotton-Rajkot (Dec 20)	18520.0	0.2
Discount over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	5650.0	-4.1
Jeera Unjha (Dec 20)	15875.0	-2.2
Coriander-Kota (Dec 20)	6790.0	-2.1
Moong-Merta City (Dec 20)	6700.0	-1.6
Paddy-Basmati-Karnal (Dec 20)	3108.0	-1.3
Crude Palm Oil Kandl (Dec 31)	690.3	-0.3

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	98 (98)
Aluminium ingots /kg	135 (135)
Brass sheet cutting /kg	312 (313)
Brass utensil scraps/kg	295 (296)
Copper heavy scrap /kg	411 (412)
Copper utensil scraps/kg	389 (387)
Copper wire bar /kg	444 (444)
Lead ingots /kg	152 (152)
Nickel Cathodes /kg	1010 (1010)
Tin slabs /kg	1255 (1250)
Zinc slabs /kg	185 (184)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10714 (10714)
DCH - 32 /Qtl	11360 (11360)
Jaydhar /Qtl	10011 (10011)
Shankar- 6 /Qtl	11220 (11220)

Source:Cotton Association of India

Oil	Mumbai
Castor FSG /10kg	867 (855)
Castor Comm /10kg	857 (845)
Ricebran oil/10kg	760 (760)
Groundnut oil /10kg	1030 (1020)
Linseed oil /10kg	845 (845)
Karanji /10kg	760 (760)
Palm oil /10kg	770 (768)
Sunflower exp ref /10kg	835 (830)
Sunflower oil exp /10kg	790 (790)
Soyabean ref / 10kg	820 (810)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3332-3572 (3332-3582)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	58.5 (58.43)
Brent Crude (UK)	63.18 (62.86)
Brent Crude (WTI)	58.43 (58.43)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	2.43 (2.4)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	240.51 (239.98)
Naptha spot /Rs/MT	45170 (45170)
LSHS spot/ M.T.	36150 (36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950 (33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	38028 (38184)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	38181 (38338)
Silver.999/ kg	43980 (44700)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18467.00	18491.55
Alumini-Mumbai (M)	1 K	140.80	138.65
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1895.00	1900.00
Barley Jaipur (N)	1 Q	2117.95	2119.30
Brass-Jamnagar (M)	1 K	312.50	303.40
Cardamom-Vand. (I)	1 K	2883.00	2900.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4084.65	4121.45
Castor Seed-Kadi (N)	X	3987.50	4075.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4307.65	4305.15
Chana Delhi (N)	1 Q	4500.00	4459.40
Chana-Akola (N)	X	4428.15	4400.00
Coriander-Gondal (N)	X	6600.00	6700.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6812.50	6848.75
Coriander-Kota (N)	1 Q	6875.90	6936.55
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	1996.50	1987.80
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	1950.00	1958.35
Cotton-Kadi (N)	1 B	18465.25	18429.40
CPO-Kandla (M)	10 K	687.00	689.30
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	687.45	692.05
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	886.50	883.60
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1543.05	1538.05
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3480.45	3469.20
Gold Ahm (M)	10 G	38162.00	38042.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	30652.00	30556.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3833.00	3819.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7298.95	7190.45
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	3948.35	3900.00
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3900.00	3900.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1017.85	1014.05
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	93.60	93.65
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	16850.00	16850.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16355.25	16237.50
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1007.80	1009.40
Kapas-Rajkot (N)	X	993.50	1003.15
Lead Mum (M)	1 K	156.70	158.40
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1910.65	1920.65
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2230.00	2250.15
Maize-Erode (N)	X	2103.75	2044.60
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2150.00	2121.25
Maize-Sangli (N)	X	2000.00	2010.90
Moong-Merta City (N)	1 Q	6737.50	6805.55
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4565.75	4540.00
Nickel Mumbai (M)	1 K	1010.10	994.00
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3100.00	3150.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3187.00	3186.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	350.00	350.00
Pepper-Kochi (N)	1 Q	35026.00	35000.00
Rape mustards-Patan (I)	20 K	787.00	797.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	2100.50	2088.50
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	745.00	754.65
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	826.15	829.40
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	819.55	822.55
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	825.00	834.00
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13000.00	13000.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13025.00	13058.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	44671.00	43892.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4081.00	4081.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4007.50	4018.85
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4090.50	4090.50
Soy Bean-Akola (N)	X	4108.00	4131.00
Soymeal Indore (N)	1 T	33500.00	33367.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	824.80	826.60
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	27910.00	27810.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	29040.00	28900.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	26000.00	25940.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3280.00	3275.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3380.95	3385.70
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3296.65	3297.50
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3438.10	3428.55
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3285.00	3281.65
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3130.45	3132.10
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	5900.00	5890.65
Wheat Delhi (N)	1 Q	2250.00	2251.65
Wheat Kota (N)	1 Q	2124.00	2125.00
Wheat New Indore (N)	1 Q	2200.00	2188.75
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2073.75	2072.50
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2191.25	2192.50
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	4704.60	4780.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	184.20	184.60

* as on Dec 04, 19

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

DAY SESSION

दिवस सत्र (गुरुवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19100, 19150, 19020, 19070	1539	235	9026
Jan 31	19210, 19290, 19180, 19220	238	44	2474
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Dec 20	1949, 1970, 1905, 1925	24230	1473	31330
Jan 20	1966, 1992, 1929, 1950	45380	2782	53100
Feb 20	1985, 2008, 1955, 1971	5210	427	21640
Mar 20	2019, 2031, 1980, 1992	480	46	2390
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1066.5, 1071.5, 1066.5, 1070	72	17	632
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1068, 1072, 1065, 1071	616	328	3808
Grains				
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
May 20	1695, 1695, 1695, 1695	200	4	810
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	3956, 4058, 3914, 4044	21270	2388	28710
Jan 20	3988, 4098, 3952, 4084	47045	5170	66540
Feb 20	4028, 4128, 3990, 4120	1090	187	1780
Mar 20	4040, 4040, 4040, 4040	25	1	25
Maize Kharif NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	2032, 2032, 2031, 2031	1100	3	4600
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4044, 4124, 4038, 4112	7880	806	25850
Jan 20	4084, 4168, 4076, 4154	8140	923	24475
Feb 20	4110, 4152, 4090, 4130	105	21	3715
Mar 20	4100, 4170, 4100, 4138	270	39	2970
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	689.4, 692.9, 687, 692.6	11020	791	46100
Jan 31	690, 692.7, 686.8, 692.3	4770	381	19310
Feb 28	694.5, 697, 690.5, 695.9	1350	116	1960
Mentha Oil MCX(1 K)				
Dec 31	1300.5, 1303, 1286, 1299.8	206.64	483	271.8
Jan 31	1308.5, 1312, 1296.5, 1304.2	10.08	18	27.72
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4373, 4395, 4352, 4392	7920	625	22290
Jan 20	4400, 4430, 4381, 4426	9140	701	9240
Feb 20	4350, 4388, 4350, 4388	30	3	130
Apr 20	4280, 4350, 4280, 4310	310	23	1300
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	828.4, 833.6, 826.2, 832.8	11535	1124	23340
Jan 20	830, 834, 826.2, 832.4	15140	1602	47495
Feb 20	827.2, 830.4, 823.4, 828.8	2575	196	14100
Mar 20	827, 827, 827, 827	5	1	35
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4110, 4114, 4078, 4098	16235	1950	49985
Jan 20	4142, 4144, 4106, 4130	31425	3319	154775
Feb 20	4168, 4168, 4134, 4152	7045	953	92165
Mar 20	4170, 4190, 4156, 4174	1870	305	27070
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	7135, 7324, 7052, 7297	8300	1079	13450
Jan 20	7256, 7425, 7151, 7390	17305	2473	53120
Feb 20	7294, 7520, 7270, 7481	550	94	1030
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4400, 4450, 4393, 4419	9650	780	23810
Jan 20	4415, 4475, 4415, 4448	12300	952	35420
Mar 20	4391, 4415, 4380, 4400	80	8	2380
Apr 20	4331, 4350, 4331, 4350	30	3	410
May 20	4430, 4430, 4430, 4430	10	1	10
Moong-Mertacity NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	6700, 6700, 6700, 6700	25	1	25
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Dec 13	2999, 3032, 2989.8, 3006.7	0.7	7	1.6
Jan 15	2860, 2950, 2860, 2944.9	3	29	10.4
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Dec 20	6620, 6800, 6610, 6790	2100	177	6410
Jan 20	6530, 6660, 6530, 6615	1330	120	5890
Apr 20	6929, 6999, 6900, 6939	190	15	2660
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Dec 20	15860, 15985, 15760, 15875	1116	317	1389
Jan 20	15805, 15860, 15745, 15780	1113	286	1998
Mar 20	15800, 15800, 15800, 15800	15	5	204
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Dec 20	5612, 5702, 5610, 5650	2750	329	7660
Mar 20	5870, 5950, 5842, 5878	1770	207	4000
Apr 20	5932, 5988, 5850, 5884	475	80	1765

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	133.1, 133.45, 132.7, 132.8	3660	605	9115
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	133.15, 133.5, 132.7, 132.8	1802	1492	3468
Jan 31	134.3, 134.3, 133.8, 133.9	97	75	264
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	430.85, 432.4, 430.15, 431.55	12790	4257	16462.5
Jan 31	435.7, 436.95, 435.05, 436.25	150	58	852.5
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	152.95, 153.45, 152.6, 152.95	6915	1176	7055
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	153.1, 153.4, 152.75, 153	2661	2276	3055
Jan 31	153.25, 153.5, 153, 153.2	46	45	130
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	972.5, 976.4, 965.8, 969.9	8991	5316	3502.5
Jan 31	972.5, 973.8, 965.8, 967.7	180	116	225
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	183.75, 184.95, 183.4, 183.95	26945	4368	17390
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	184.4, 185.15, 183.65, 184.15	9247	7133	5409
Jan 31	183.8, 184.75, 183.15, 183.65	609	407	1369

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Feb 28	184.5, 184.5, 184, 184.35	3	3	5
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Dec 05	38850, 38850, 38192, 38326	0.01	7	0.08
Feb 05	38149, 38237, 38008, 38026	5.57	4765	17.17
Apr 03	38182, 38260, 38062, 38096	0.1	98	1.91
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30570, 30687, 30570, 30598	0	157	0
Jan 31	30630, 30672, 30611, 30652	0	15	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Dec 05	38245, 38245, 38075, 38113	0	11	0
Jan 03	38176, 38270, 38063, 38079	0.66	5634	0.86
Feb 05	38142, 38249, 38035, 38050	0.11	988	0.21
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3885, 3898, 3878, 3880	0	735	0.01
Jan 31	3858, 3874, 3858, 3867	0	114	0
Silver MCX(1 K)				
Dec 05	44200, 45287, 43850, 44000	1.14	23	1.32
Mar 05	44525, 44688, 44270, 44308	252.81	6806	396.99
May 05	45102, 45183, 44825, 44867	0.75	25	5.37
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	44510, 44712, 44309, 44350	26	17215	30.99
Apr 30	45134, 45225, 44849, 44872	0.7	567	1.14
Aug 31	46015, 46015, 46015, 46015	0	1	0
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	44543, 44713, 44300, 44336	80.28	12764	60.48
Apr 30	45110, 45233, 44848, 44870	1.01	183	0.89

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	172.6, 175, 170.3, 174	62788mb	29177	32230mb
Jan 28	171, 173.9, 170, 172.8	5050mb	2733	8766mb
Feb 25	166.8, 168.8, 165.3, 167.8	448mb	339	1873mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Dec 18	4167, 4184, 4149, 4172	8571bl	42490	2961bl
Jan 17	4167, 4188, 4155, 4176	202bl	1605	181bl
Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)				
Dec 18	4179, 4194, 4149, 4172	1812bl	73049	675bl

सायं सत्र (बुधवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19050, 19140, 18950, 19120	3618	588	8729
Jan 31	19200, 19280, 19120, 19250	638	136	2402
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1068, 1069, 1059.5, 1067	344	74	644
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1067, 1069, 1061.5, 1068	863	457	3796
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	682.1, 689.7, 681.2, 688.8	17680	1195	47340
Jan 31	682.5, 690, 682, 688.7	8290	583	18410
Feb 28	687, 694.1, 685.5, 693.1	940	92	1250
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	825, 830.6, 822.2, 828	10645	1082	26115
Jan 20	828, 833, 826, 829.8	12725	1206	46000
Feb 20	822.6, 829.6, 822.4, 827.2	3185	257	12775

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	133.55, 133.8, 132.65, 133.2	13235	1877	8945
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	133.5, 133.75, 132.65, 133.15	5166	4009	2970
Jan 31	134.6, 134.65, 133.85, 134.1	306	246	267
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	429.3, 432.5, 427.7, 431.1	32882.5	10836	14600
Jan 31	433.95, 437.15, 432.7, 436	695	260	797.5
Feb 28	439, 439, 439, 439	25	8	25
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	152.55, 153.35, 151.8, 152.75	20940	3428	5725
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	152.55, 153.35, 152.05, 152.8	8546	7058	2598
Jan 31	152.8, 153.5, 152.4, 153.1	153	150	115
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	979.4, 987.7, 968, 969.7	22003.5	13087	2544
Jan 31	978, 985.9, 967.1, 968.6	291	188	186
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	181.75, 184.5, 181.65, 184	62985	9991	15320
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	182.6, 184.85, 182.15, 184.2	19060	15103	4293
Jan 31	182.85, 184.35, 182.1, 183.85	1445	1069	1255
Feb 28	183.5, 184, 183.5, 183.8	5	5	4
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Dec 05	38331, 38450, 38140, 38176	0.07	58	0.09
Feb 05	38330, 38467, 38031, 38094	14.25	12142	17.02
Apr 03	38386, 38498, 38083, 38128	0.23	211	1.85
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30701, 30825, 30570, 30592	0.01	651	0
Jan 31	30649, 30725, 30600, 30620	0	31	0
Feb 28	30373, 30772, 30373, 30678	0	6	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Dec 05	38563, 38563, 38081, 38188	0.01	41	0.04
Jan 03	38344, 38460, 38077, 38138	1.94	16345	0.79
Feb 05	38301, 38464, 38054, 38114	0.34	2858	0.19
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3888, 3900, 3876, 3881	0.01	1702	0.01
Jan 31	3880, 3900, 3863, 3866	0	429	0
Feb 28	3870, 3870, 3866, 3869	0	3	0
Silver MCX(1 K)				
Dec 05	44949, 45100, 44100, 44392	1.02	22	6.3
Mar 05	45361, 45678, 44301, 44430	946.29	25189	358.32
May 05	45874, 46169, 44822, 44914	8.88	290	5.19
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	45315, 45687, 44351, 44459	84.56	56005	26.69
Apr 30	45900, 46173, 44906, 45028	3.81	2785	1.03
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	45260, 45690, 44337, 44454	260.96	40997	50.06
Apr 30	45916, 46161, 44899, 45014	4.02	707	0.83

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	177.5, 177.5, 169.6, 171.3	172880mb	79054	29594mb
Jan 28	176.7, 176.7, 168.8, 170.3	13560mb	6866	8901mb
Feb 25	169.5, 169.8, 164.6, 165.5	1341mb	898	1870mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Dec 18	4048, 4195, 4041, 4184	35687bl	167396	2120bl
Jan 17	4062, 4199, 4050, 4188	856bl	6611	180bl
Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)				
Dec 18	4042, 4200, 4041, 4184	7697bl	284523	551bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

बीएस बातचीत

'उपभोक्ता सर्वेक्षण नहीं हो रद्द'

कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान के पूर्व निदेशक **विमल कुमार राय** ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) के चेयरमैन का पदभार ऐसे समय संभाला है जब आधिकारिक आंकड़ों की स्वायत्तता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राय ने अपने पहले साक्षात्कार में **सोमेश झा** के साथ हाल के उस विवाद पर बातचीत की, जिसमें सरकार ने उपभोक्ता सर्वेक्षण रिपोर्ट को रद्द करने का फैसला किया है। बातचीत के अंश :

चित्रांकन : अजय मोहंती

सरकार ने हाल में 2017-18 की उपभोक्ता सर्वेक्षण रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डालने का फैसला किया है। इस बारे में आपका क्या कहना है?

हम सर्वेक्षण रिपोर्ट को रद्द करने के पक्ष में नहीं हैं। हम रिपोर्ट में कुछ निश्चित कैविएट जोड़ने और इसे दो महीने के भीतर सार्वजनिक करने की संभावनाओं के बारे में विचार कर रहे हैं। यह हमारा लक्ष्य है। सरकार की चिंता यह है कि ये अनुमान वास्तविक नजर नहीं आ रहे हैं। हम इस मुद्दे की जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस मामले की जांच के लिए दो-तीन समिति गठित करने का फैसला किया है।

क्या आप यह मानते हैं कि सरकार का एनएससी से विचार-विमर्श न करना और खुद ही रिपोर्ट को रद्द कर देना सही था?

मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं केवल अपने कार्यों की जिम्मेदारी ले सकता हूं। मैं अन्य लोगों के काम पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। हो सकता है कि सरकार ने यह सोचा हो कि ये अनुमान वास्तविक नजर नहीं आ रहे हैं।

लेकिन इससे तो एनएससी की स्वायत्तता कम हो जाती है...

सरकार एनएससी को ज्यादा स्वायत्तता और शक्ति देने के लिए एक नया विधेयक लाने की कोशिश कर रही है। इस समय एनएससी की स्वायत्तता का सवाल स्पष्ट नहीं है और सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। सरकार इसके लिए नया कानून बनाने की दिशा में काम कर रही है।

अभी तक यह परंपरा रही है कि कोई भी फैसला लिए जाने से पहले सर्वेक्षण को मंजूरी के लिए एनएससी के पास भेजा जाता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ऐसा नहीं हुआ है...

हम नई संस्था हैं और यह सर्वेक्षण काफी पहले किया गया था। यह संभव है कि सरकार ने यह माना हो कि एनएससी को सर्वेक्षणों की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी नहीं है।

क्या आपका यह मानना है कि एनएससी सर्वेक्षणों को मंजूरी देने वाला अंतिम अथॉरिटी होना चाहिए।

मेरे लिए इस पर टिप्पणी करना मुश्किल है। इस पर सरकार को फैसला लेना होगा और हम उसका अनुसरण करेंगे।

क्या बहुत से अर्थशास्त्रियों के तर्कों की तरह आपका भी यह मानना है कि उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षण के यूनिट स्तरीय आंकड़े तत्काल सार्वजनिक किए जाने चाहिए?

एक शिक्षाविद के रूप में मैं सभी सर्वेक्षणों के यूनिट स्तरीय आंकड़ों को जारी करने के पक्ष में हूं और हम उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षण के यूनिट स्तरीय आंकड़ों को जारी कर खुशी का अनुभव करेंगे।

क्या आपका मानना है कि एनएसओ के सर्वेक्षणों में आंकड़ों की गुणवत्ता से संबंधित खामियां हैं?

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कुछ खामियां पाई हैं। हम इनके समाधान की कोशिश कर रहे हैं।

क्या आप इन खामियों में से कुछ पर प्रकाश डाल सकते हैं?

उदाहरण के लिए जब आप घरेलू उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षण करते हैं तो सरकारी योजनाओं के जरिये प्राप्त सामाजिक सुरक्षा लाभों में कुछ खर्चों को शामिल नहीं किया जाता है। अगर उपभोक्ता को ज्यादा सामाजिक सुरक्षा सहायता मिलती है तो उनका उन चीजों पर खर्च घटेगा, जो उन्हें सामाजिक सुरक्षा के तहत मिल रही हैं। अगर किसी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) व्यक्ति को अत्यधिक रियायती दरों पर चावल मिलता है तो स्वाभाविक है कि उसका व्यय कम नजर आएगा। हालांकि यह डेटा की गुणवत्ता से संबंधित खामी नहीं है, लेकिन इन सभी कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

राज्यों द्वारा संचालित स्वास्थ्य से संबंधित बहुत से सरकारी कार्यक्रम हैं। यह सर्वेक्षण दर्शाता है कि संभवतया स्वास्थ्य खर्च में कमी आई है। हालांकि यह जमीनी हकीकत पर गलत नजर आ रहा है, लेकिन हम इसका कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब अन्य सर्वेक्षण सीएपीआई (कंप्यूटर की मदद से व्यक्तिगत साक्षात्कार) के जरिये किए जा रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति को इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि सर्वेक्षणकर्ता कैसे इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी समस्या सर्वेक्षण के फील्ड वर्क के लिए ठेके के कामगारों का इस्तेमाल करना है। सर्वेक्षण के बाद ठेके की अवधि खत्म होने को आती है तो किसी स्तर पर खामी मिलने की स्थिति में ऐसे सर्वेक्षणकर्ताओं से संपर्क करना मुश्किल होता है। हम इन सभी कारकों के सभी सर्वेक्षणों पर पड़ने वाले असर की जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमें सबक मिला है। एक अहम कारक यह देखना है कि एक अवधि में कोएफिशिएंट ऑफ वैरिएशन में कितना अंतर आता है। अगर यह अधिक है तो अनुमान विश्वसनीय नहीं हैं।

आपने इन कुछ दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या योजना बनाई है?

हम तकनीक की मदद ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर परिवार यह जानकारी देते हैं कि उन्होंने उपभोग के लिए निश्चित मात्रा में आटा खरीदा है तो हम उनसे आटे की कीमत पूछने के बजाय कीमतों के आंकड़े मंडी जैसे अन्य स्रोतों से ले सकते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो कीमत पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौजूदा प्रश्नावली बहुत लंबी है और प्रत्युत्तरदाता 10-15 मिनट बाद अधीर हो जाते हैं। इसलिए सवाल यह पैदा होता है कि क्या हम कुछ आंकड़े प्रत्युत्तरदाताओं से पूछने के बजाय अन्य स्रोतों से हासिल कर सकते हैं।

कृत्रिम मेधा पर समिति की रिपोर्ट हुई सार्वजनिक

नेहा अलावधी

- पिछले वर्ष मंत्रालय ने एआई के अनुप्रयोग को लेकर बनाई थीं चार समितियां
- समिति को विभिन्न क्षेत्रों में एआई अनुप्रयोग, कानूनी, नियामकीय, नैतिक तथा साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर देनी थी रिपोर्ट
- रिपोर्ट में नैशनल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस रिसोर्स प्लेटफॉर्म बनाने की अनुशंसा की गई

देश में कृत्रिम मेधा (एआई) के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए चार समितियों के गठन के करीब एक साल बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गुरुवार को समिति की सिफारिशों के साथ संबंधित रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी।

मंत्रालय ने पिछले वर्ष नागरिकों से संबंधित क्षेत्रों में एआई के अनुप्रयोग के लिए चार समितियों का गठन किया था। इनमें डेटा प्लेटफॉर्म विकसित करना, कौशल विकास तथा कौशल उन्नयन, शोध एवं विकास के साथ साथ कानूनी, नियामकीय, नैतिक और साइबर सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों पर काम करना है। नीति आयोग ने पिछले वर्ष जून माह में 'कृत्रिम मेधा के लिए राष्ट्रीय रणनीति' नामक चर्चापत्र जारी किया था।

एआई के साथ प्लेटफॉर्म तथा डेटा से संबंधित पहली रिपोर्ट में कहा गया, 'रिपोर्ट भारत में नैशनल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस रिसोर्स प्लेटफॉर्म (एनएआईआरपी) के विकास की अनुशंसा करती है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो सार्वजनिक रूप से साझा करने योग्य डेटा, सूचना, उपकरण, साहित्य, समाधान आदि को एक साथ लाएगा ताकि बड़ी संख्या में लोगों को व्यक्तिगत रूप से सक्षम बनाया जा सके। इसके सहयोग से क्षमता निर्माण करना और ऐसा माहौल बनना जिससे समाज को लाभ हो, राष्ट्र समृद्ध हो और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बेहतर हो सके।' राष्ट्रीय कृत्रिम मेधा केंद्र स्थापित करने की सरकार की योजना अटकी हुई है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि इस मामले में नीति आयोग या आईटी मंत्रालय में से कौन सा विभाग पहल करेगा। हालांकि रिपोर्ट को जारी होने में देरी की वजह से मंत्रालय द्वारा बनाई गई समितियों के कुछ सुझाव अब बेमानी हो सकते हैं।

प्रमुख क्षेत्रों में राष्ट्रीय मिशन के तौर पर एआई तकनीक का लाभ उठाने के लिए समिति ने प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित मिशनों के लिए एक रोड मैप तैयार करने की सिफारिश की। इसके अलावा समिति ने बताया कि मंत्रालयों एवं विभागों के उपलब्ध डेटा को अच्छी तरह से परिभाषित स्वरूपों में एक साझा मंच पर लाया जाना चाहिए। तकनीकी क्षमताओं, कौशल विकास एवं कौशल उन्नयन, शोध एवं विकास तथा प्रमुख नीतिगत मुद्दों के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नियंत्रण के साथ सार्वजनिक डेटा उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है। इसमें कहा गया, 'प्रतिबंध के बजाए सहायक नीतियों तथा नियामकों के साथ एआई का उपयोग किया जाए और एआई के विस्तार पर रोक लगाने वाले नियमों को हटाया जाए।' समिति ने एआई तकनीक के कानूनी, सुरक्षा और नैतिकता संबंधी मुद्दों की जांच करने का सुझाव दिया है। समिति ने तकनीकी विकास, नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एआई आधारित साइबर सुरक्षा चुनौतियों का आयोजन और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का सुझाव दिया है।

सोशल मीडिया खातों का जरूरी हो सकता है सत्यापन

प्रस्तावित निजता संबंधी विधेयक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पहचान के सत्यापन से जुड़े नियम लाए जा सकते हैं जिससे फर्जी खबरों के विस्तार पर लगाम लगाने के प्रयास किए जा सकें। गुरुवार को दो सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस नियम के चलते भारत में लाखों उपयोगकर्ताओं वाली फेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और चीनी ऐप टिकटोक सहित विभिन्न सोशल मीडिया कंपनियों के लिए तकनीकी एवं नीतिगत चुनौतियां सामने आ सकती हैं। कंपनियों को ग्राहक द्वारा अपनी पहचान साबित करने के लिए एक प्रणाली बनानी होगी जिससे वे सार्वजनिक तरीके से इसे प्रदर्शित कर सकें। यह ट्विटर द्वारा लोकप्रिय हस्तियों एवं राजनेताओं के खातों को सत्यापित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली नीले मार्क की तरह हो सकता है।

हालांकि सूत्र ने बताया कि सत्यापन प्रक्रिया उपयोगकर्ता के लिए वैकल्पिक होगी।

निजी डेटा संरक्षण विधेयक का पहला मसौदा पिछले वर्ष सार्वजनिक किया गया था और शीर्ष तकनीकी कंपनियां तथा उद्योग इसे लेकर काफी गंभीर हैं। संभावना है कि इसके चलते अधिकांश इंटरनेट कंपनियों को भारतीय उपयोगकर्ताओं के आंकड़ों को सहेजने, एक जगह से दूसरी जगह भेजने और अन्य प्रक्रियाओं में अहम बदलाव करने पर सकते हैं। पहचान सत्यापन की आवश्यकता को विधेयक के हालिया मसौदे में शामिल किया गया है और यह वैश्विक स्तर पर फर्जी खबरों को रोकने के प्रयासों के तौर पर अहम कदम साबित हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिकांश फर्जी खबरें फर्जी खातों से ही फैलाई जाती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया, 'इसे लाने के पीछे विचार यह है कि फर्जी खबरों और ऑनलाइन ट्रोलिंग पर लगाम लगाई जा सके।'

सूत्र ने बताया कि निजता विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और इसे जल्द ही संसद में पेश किया जा सकता है। हालांकि इसे पारित करना इतना आजान नहीं होगा क्योंकि इस बात का काफी संभावना है कि इसे संसदीय समिति या किसी पैनल के पास समीक्षा के लिए भेज दिया जाए। वर्ष 2017 से देश में फर्जी खबरें और अफवाहें सोशल मीडिया पर बहुत अधिक प्रसारित हो रही हैं और इनके चलते देशभर में 30 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। *रॉयटर्स*

नागरिकता बिल पर विपक्ष का बड़ा हिस्सा लामबंद

अर्चिस मोहन

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) के खिलाफ लामबंद होने का संकेत देते हुए यह तय किया है कि वे अगले कुछ दिनों तक इस प्रस्तावित कानून की 'विभाजनकारी' प्रकृति के बारे में जागरूकता फैलाने की मुहिम चलाएंगे।

विपक्षी दल अब अपना ध्यान राज्यसभा में इस विधेयक को रोकने में लगाने के बजाय जन-जागरूकता फैलाने पर लगाना चाहते हैं। इस मकसद से विपक्षी नेताओं की आज संसद के भीतर बैठक भी हुई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के कक्ष में हुई इस बैठक में विपक्ष की रणनीति पर चर्चा हुई। तमाम विपक्षी नेता इस बात पर सहमत दिखे कि राज्यसभा में अधिकांश क्षेत्रीय दलों के ढुलमुल रवैये के चलते उनके जीत की संभावना काफी कम है। उनका मानना था कि क्षेत्रीय दल या तो विधेयक के समर्थन में वोट करेंगे या फिर वे मतदान से अलग रहने की रणनीति अपनाएंगे। ऐसे में कुछ दलों के दम पर विधेयक को रोका नहीं जा सकता है। जहां तक लोकसभा का सवाल है तो वहां पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अकेले ही स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है लिहाजा इस विधेयक को लटकाने के बारे में विपक्ष सोच भी नहीं सकता है।

कांग्रेस ने कहा है कि वह नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करेगी। इसी तरह वामदलों, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और आम आदमी पार्टी (आप) ने भी खुले विरोध की बात कही है। तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी इसके मुखर आलोचकों में शुमार हैं। कांग्रेस के कुछ गठबंधन सहयोगी- मसलन, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) भी इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये सभी विपक्षी दल मिलकर भी विधेयक को पारित होने से नहीं रोक सकते हैं।

हालांकि भाजपा की अगुआई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पास भी राज्यसभा में अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल है लेकिन उसे पूरा यकीन है कि गठबंधन के बाहर के कुछ क्षेत्रीय दलों के समर्थन से वह इसे पारित करा लेगा। विपक्ष ने तय किया है कि वे चर्चा में भागीदार बनेंगे लेकिन विधेयक पर मतदान के समय वॉकआउट कर जाएंगे।

भाजपा ने नागरिकता विधेयक पर क्षेत्रीय दलों का समर्थन हासिल करने की कवायद शुरू भी कर दी है। भाजपा के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि बीजू जनता दल (बीजद), तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस), वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगुदेशम पार्टी (तेदेपा) विधेयक का समर्थन कर सकते हैं। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों की छोटी-छोटी पार्टियां भी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। इसके लिए सिक्किम समेत तमाम पूर्वोत्तर राज्यों के नेताओं को गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात के लिए बुलाया भी था। विपक्षी सूत्रों का मानना है कि हाल ही में राजग से अलग हो चुकी शिवसेना भी अपनी हिंदुत्ववादी छवि को बनाए रखने के लिए इस विधेयक के पक्ष में मतदान कर सकती है।

अर्थव्यवस्था पर मोदी की चुप्पी असामान्य: चिदंबरम

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर असामान्य रूप से मौन हैं और उन्होंने अपने मंत्रियों को लोगों को बेवकूफ बनाने तथा शेखी बघारने के लिए छोड़ दिया है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार का मानना है कि इस वित्त वर्ष के सात माह बाद भी अर्थव्यवस्था के सामने आ रही समस्याएं चक्रीय हैं।

आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में 105 दिन तक तिहाड़ जेल में बंद रहने के बाद बुधवार को जमानत पर रिहा हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लिया।

उन्होंने कहा, 'सरकार को अर्थव्यवस्था की कोई खबर नहीं है। वह नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण जीएसटी, कर आतंकवाद जैसी भयानक गलतियों का बचाव करने पर अड़ी हुई है।' चिदंबरम ने कहा, 'प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था पर असामान्य रूप से मौन हैं। उन्होंने इसे अपने मंत्रियों पर छोड़ दिया है जो लोगों को बेवकूफ बनाने तथा शेखी बघारने में लगे हैं। अर्थव्यवस्था को सुस्ती से बाहर निकाला जा सकता है लेकिन यह सरकार ऐसा करने में अक्षम है।

चिदंबरम ने प्याज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टिप्पणी पर चुटकी लेते हुए पूछा कि क्या वह एवोकैडो खाती हैं? दरअसल, सीतारमण ने कहा था कि उनके परिवार को प्याज बहुत पसंद नहीं है। उल्लेखनीय है कि बुधवार को एक सांसद ने सीतारमण से पूछा कि क्या वह प्याज खाती हैं, इस पर उन्होंने कहा था, 'मेरे परिवार में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता।'

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम पर अदालत

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने महंगाई के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लिया

की जमानत शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने जमानत पर रिहा होने के अगले दिन ही अदालत के फैसले पर टिप्पणी कर उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है। जावड़ेकर ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं को बताया, 'उच्चतम न्यायालय ने चिदंबरम को जमानत देते हुए कहा था कि वह विचाराधीन मामले के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, लेकिन चिदंबरम ने आज यह बयान दिया कि बतौर मंत्री उनका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है।'

चिदंबरम ने जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वहां के लोगों की आधारभूत स्वतंत्रताओं को दबाने की नीति गलत है। *भाषा*

मुफ्त योजनाओं से पानी अभियान का टकराव

केजरीवाल सरकार मुफ्त में योजनाओं पर दांव लगा रही है तो वहीं भाजपा की रणनीति लोगों को यह विश्वास दिलाने की है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के शासन में उनके और उनके अपनों की जान खतरे में है

साई मनीष

इस बात में कोई संदेह नहीं कि दिल्ली की जनता जिस हवा में सांस ले रही है उसको लेकर उनके मन में डर है। अब विधानसभा चुनाव होने में जब कुछ महीने शेष रह गए हैं तब ऐसा लग रहा है कि भाजपा लोगों के दिमाग में इस बात को लेकर भी डर पैदा करने में सफल हो गई है कि उनके पीने का पानी साफ नहीं है। भाजपा लोगों को बता रही है कि दिल्ली सरकार की ओर से मुहैया कराए जा रहे पानी में सामान्यत: मानव मल में पाए जाने वाले कॉलीफार्म जीवाणु, औद्योगिक कचरे में शामिल कैंसर कारक फेनोलिक उत्पाद, त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाला एनीओनिक डिटर्जेंट है और इसी तरह के बहुत से गंदे मिश्रण और बदबूदार पदार्थों की मिलावट है।

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की ओर से जारी किए गए भारतीय मानक ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली एकमात्र ऐसा शहर है जहां पानी का एक भी नमूना पीने योग्य नहीं पाया गया है। भाजपा नेता मनोज तिवारी और गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल पर इस मुद्दे को लेकर धावा बोल दिया है। इससे पहले केजरीवाल ने पासवान पर पानी शुद्ध करने वाली कंपिनयों से अपने कारोबारी हित जुड़े होने का आरोप लगाया था। इसके बाद भाजपा ने केजरीवाल पर जवाबी हमले तेज कर दिए। भाजपा ने इस मामले में और आगे बढ़कर गंदे पानी की रिपोर्ट करने के लिए हेल्पलाइन नंबर तक जारी कर दिया।

भाजपा की रणनीति बहुत स्पष्ट है। वह लोगों को यह यकीन दिलाना चाहती है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के शासन में लोगों की अपनी और उनके अपनों की जान खतरे में है। लेकिन अगले वर्ष केजरीवाल की पार्टी को सत्ता में वापसी

भाजपा पानी की स्वच्छता से जुड़ी विभिन्न रिपोर्ट के जरिये जनता के बीच जा रही है

करने से रोकने के लिए डर को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की भाजपा की रणनीति कितनी प्रभावी होगी फिलहाल यह बता पाना मुश्किल है। भाजपा की चुनौती इन मतदाताओं को यह समझाने की होगी कि पानी जैसे बुनियादी जरूरत के लिए भुगतान करने के बावजूद केजरीवाल सरकार उन्हें पीने का ऐसा पानी मुहैया नहीं करा पा रही है जिससे उनका या उनके परिवार के लोगों की सेहत पर बुरा असर न पड़े। या उस संबंध में लोगों को यह समझाया जाए कि हर परिवार को जो मुफ्त में पानी दिया जा रहा है उससे लोग बीमार पड़ सकते हैं।

दूसरी तरफ केजरीवाल ने अपने पानी की राजनीति को ही आगे बढ़ाया है। केजरीवाल सरकार पानी या तो मुफ्त या अत्यधिक कम दर पर मुहैया करा रही है। 2013 में जब आम आदमी पार्टी (आप) कांग्रेस के समर्थन से पहली बार सत्ता में आई थी तब केजरीवाल ने शहर के हर घर को 20,000 लीटर पानी मुफ्त में देने की घोषणा की थी। जब आप 2015 में एकतरफा जीत हासिल कर सत्ता में लौटी तो उसने इस योजना को आगे बढ़ाया। उसके बाद इस साल अगस्त में केजरीवाल ने पानी के बिलों को माफ करने की घोषणा की जिससे करीब 13 लाख घरों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है।

चुनावों से कुछ महीने पहले केजरीवाल की ओर से एक के बाद एक मुफ्त घोषणाओं से समाज के सभी वर्गों को फायदा पहुंच रहा है। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली बिल, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, सड़क दुर्घटना के घायलों का मुफ्त इलाज और शहर के निवासियों के लिए बिना किसी आर्थिक भेदभाव के सरकारी और पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में मुफ्त सर्जरी से लेकर चुनिंदा जगहों पर मुफ्त में वायरलेस इंटरनेट की सुविधा तक शामिल है। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मेट्रो में मुफ्त यात्रा के प्रस्ताव की बात कह कर तूफान ला दिया था जो आगे चलकर केंद्र सरकार के स्तर पर जाकर फंस गई।

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की वरिष्ठ फेलो रूमी ऐजाज ने कहा, 'सच्चाई यह है कि आप दिल्ली में नल का पानी नहीं पी सकते हैं। दिल्ली सरकार भी अपने आधिकारिक बैठकों में नल का पानी नहीं रखती है। लेकिन खराब हवा और पानी को लेकर राजनीति का आप पर मामूली असर ही होगा। दिल्ली में अधिकांश मतदाता मध्य वर्ग या कम आय समूहों के हैं। जब उन्हें इतनी सुविधाएं मुफ्त मिल रही हैं तो वे खुशी खुशी थोड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं। लोगों में मुफ्त बिजली और पानी मिलने को अस्थायी सुविधा के तौर पर देखने की दीर्घावधि समझ नहीं है। जब तक उन्हें ये चीजें मुफ्त में मिल रही हैं वे सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे। आप लोगों की इस भावना को भुनाने में सफल रहेगी।'

भाजपा इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। वह दिल्ली में अंतिम बार 1993 में सत्ता में आई थी। चूंकि भाजपा के पास अभी तक स्थानीय स्तर पर कोई ऐसा नेता नहीं है जो केजरीवाल की लोकप्रियता की बराबरी कर सके ऐसे में वह सरकार को वायु प्रदूषण और पानी की गुणवत्ता के मामले पर घेर रही है। वहीं केजरीवाल वायु प्रदूषण के आरोप को केंद्र सरकार की तरफ मोड़ने में सफल होते दिख रहे हैं। उन्हें इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से भी थोड़ी मदद मिली है। अब देखना होगा कि क्या केजरीवाल अपनी मुफ्त की योजनाओं के दम पर भाजपा की ओर से गंदे पानी के मामले में लगाए जा रहे आरोपों का सामना करते हुए सत्ता में बने रह पाते हैं या नहीं।